सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 180, नई दिल्ली । सोमवार, 09 सितम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

हिसाब किताब सिर्फ ऊपर वाले ने ही सही लगाया, सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया...

03 फ्री बिजली, पानी की मांग को लेकर श्री रामलीला महासंघ का धरना, प्रदर्शन
06 जी.एस.टी. काऊंसिल की बैठक पर टिकी निगाहें
08 एयरपोर्ट के आसपास मिट्टी का परीक्षण भी किया गया

दिल्ली परिवहन विभाग अपनी शाखाओं को बिना पूर्व सूचना क्यो बंद कर रहा है, क्या जनहित में या राजस्व हित में, बड़ा सवाल ?

संजय बाटला

नई दिल्ली। परिवहन विभाग के आला अधिकारी का मानना है की दिल्ली की जनता गूंगी हैं और उसके समक्ष जरा सा जनहित का नाम लेकर कुछ भी कर सकते हैं। अब तक आला अधिकारी की सोच सही निकल कर सामने आ रही है क्योंकि पहले दिल्ली परिवहन विभाग ने पूर्व सूचना दिए बिना जनहित में अधिकृत (नोटिफाइड) तीन क्षेत्रीय शाखाओं को ताले लगा दिए और बाद में उन ताला लगी क्षेत्रीय शाखाओं की जनता को कई किलोमीटर दूर अपने इच्छा की शाखा में जानें के निर्देश जारी कर दिए और दिल्ली की भोली जनता अपने घर से कई किलोमीटर दूर की शाखा में गूंगे बने अपने वाहन संबंधित कार्यों के लिए धक्के खाने पहुंचने लगे। इसी बात का फायदा उठाकर परिवहन आयुक्त ने फिर से 2 क्षेत्रीय शाखाओं को बिना पूर्व सूचना के बंद कर वहा की जनता को कई किलोमीटर दूर की शाखा में जानें को मजबूर कर दिया। दिल्ली सरकार और आयुक्त परिवहन की सोच यही समाप्त नही है विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जल्द ही दिल्ली की अन्य दो क्षेत्रीय शाखाओं को बंद कर उस क्षेत्र की जनता को भी कई किलोमीटर दूर स्थित शाखा में जानें के लिए मजबूर करने वाले हैं। इसके अतरिक्त दिल्ली के सभी श्रेणियों के व्यवसायिक वाहनों को बुराड़ी क्षेत्र जांच

कार्यालय से हटाकर वाहन जांच हेतु जबरदस्ती झुलझुली वाहन जांच केंद्र पर भेजने के आदेश कर दिए। इसके अतिरिक्त दिल्ली में व्यवसायिक श्रेणी के वाहनों के पंजीकरण हेतु कार्यरत तीनो कार्यालयो को बंद करने का आदेश करने की तैयारी पूरी कर ली गई है और सूत्रों की माने तो आज सोमवार को ही मंत्री परिवहन दिल्ली सरकार ने अपनी अध्यक्षता में इसके लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई हुई हैं। अचरज और अचंबा इस बात का है की **परिवहन मंत्री और परिवहन आयुक्त दिल्ली को पूर्ण रूप से नियम/कानून/ धाराओं/माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं अन्य सरकारी विभागों के आदेशों निर्देशों की जानकारी नहीं होगी यानी अनभिज्ञ हो सकते हैं पर क्या उनके सलाहकार, एवम्-अन्य भी इन सभी जानकारियों से अनभिज्ञ है बड़ा सवाल ?**

व्यवसायिक गतिविधियों में चलने के लिए वाहनों को कई अलग अलग श्रेणियों में वाहन चलाने के लिए परमिट की जरूरत होती है और सभी श्रेणियों के लिए अलग अलग परमिट कंडीशन, कलर कोड एवम अन्य विभागों, न्यायालयों के आदेश जारी है जिन को जाचे बिना उस श्रेणी के वाहनों का दिल्ली में पंजीकरण सम्भव नहीं पर क्या गैर तकनीकी अधिकारी या वाहन निर्माता या वाहन बिक्री करने वाले डीलर इन का पालन करवा सकते हैं या करवाएंगे बड़ा सवाल?

यहां दूसरा सवाल यह भी उठता है की बिना पूर्ण जानकारी प्राप्त किए **क्या जनता को असुरक्षित करने का अधिकार परिवहन मंत्री और परिवहन आयुक्त को प्राप्त है ?**

दिल्ली परिवहन विभाग दो श्रेणियों **(निजी और व्यवसायिक वाहनों)** के पंजीकरण और कंट्रोल के साथ जनहित मे जनता की जरूरत अनुसार सुरक्षित सवारी सेवा प्रदान करवाने के प्रति उतरदायक है पर आज परिवहन आयुक्त और परिवहन मंत्री मिलकर जो आदेश, दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं वह जनहित की जगह राजस्व हित में है। **सोचनीय बात यह है की इन सभी जानकारियों के होते हुए भी मुख्य सचिव दिल्ली, उपराज्यपाल दिल्ली, गृह मंत्रालय भारत सरकार और उच्चतम न्यायालय भारत सरकार जनता के लिए दिल्ली परिवहन विभाग के आयुक्त और विशेष आयुक्त के द्वारा जनहित विरोधी कार्यों पर अंकुश लगाने के लिए आगे क्यों नही आ रहे ?**

दिल्ली के लोगों को मिलने वाली है जल्द जाम से राहत, इसी माह शुरू होगा अप्सरा बॉर्डर फ्लाईओवर

पूर्वी दिल्ली के लोगों को इसी महीने से अप्सरा बॉर्डर से आनंद विहार तक डेढ़ किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर मिलने जा रहा है। इसके अलावा पंजाबी बाग से राजा गार्डन तक और यमुना विहार से भजनपुरा तक भी नए फ्लाईओवर बन रहे हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से दिल्लीवासियों को ट्रैफिक जाम से काफी राहत मिलेगी।

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के लोगों को इसी माह से यातायात जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलने जा रही है। इसी माह जनता को अप्सरा बॉर्डर से आनंद विहार के बीच बना डेढ़ किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर जनता को समर्पित होने जा रहा है। फ्लाईओवर बनकर तैयार है, इसी माह इसका उद्घाटन होने जा रहा है। उद्घाटन के लिए लोक निर्माण विभाग ने फाइल भेजकर सरकार से समय मांगा है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे और सरकार उन्हीं से इसका उद्घाटन कराना चाहती है।

ऐसे में इस माह के अंत तक फ्लाईओवर पर यातायात शुरू होने की पूरी संभावना है। योजना के तहत फ्लाईओवर के बीच आ रहे पेड़ों को नहीं हटाया जाएगा। पेड़ों के पास बैरीकेड्स लगाकर यातायात किया जाएगा शुरू।

पेड़ काटने के लिए पीडब्ल्यूडी ने वन विभाग से दो साल पहले अनुमति मांगी थी जो अभी तक मिल नहीं सकी है।कोरोना काल के बाद यह साल पहला ऐसा साल है जब दिल्ली को ढांचागत विकास की तीन बड़ी परियोजनाओं का लाभ मिलने जा रहा है।

आनंद विहार आरओबी और अप्सरा बॉर्डर आरओबी के बीच रोड नंबर-56 पर करीब 1440 मीटर लंबे और छह लेन के चौड़े फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। इसके निर्माण के बाद रामप्रस्थ कालोनी, विवेक विहार और श्रेष्ठ विहार लालबत्ती पर लगने वाले जाम की समस्या से लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। एनसीआरटीसी द्वारा रैपिड मेट्रो का स्टेशन बनाने के बाद इस फ्लाईओवर से होकर प्रतिदिन औसतन 1.48 लाख वाहन गुजरेंगे।

इसके बाद अगले माह तक पंजाबी बाग से राजा गार्डन तक यातायात जाम से निजात मिलने जा रही है।पंजाबी बाग स्थित दोनों सिंगल फ्लाईओवर को डबल किया जा रहा है। मौजूदा दोनों फ्लाईओवर वन-वे हैं।

दोनों फ्लाईओवर की 1-1 लेन को बढ़ाकर तीन लेन का किया जा रहा है। इसके साथ ही दोनों फ्लाईओवर के साथ 3-3 लेन के नए फ्लाईओवर तैयार किए जा रहे हैं। फ्लाईओवर के दोहरीकरण के साथ इसका पंजाबी बाग़ से राजा गार्डन तक 1400 मीटर तक विस्तार भी किया जा रहा है।

इसके बाद दिसंबर तक दिल्ली की जनता को पहला डबलडेकर फ्लाईओवर मिलने जा रहा है। यमुना विहार और भजनपुरा के बीच 1.4 किमी लंबा डबल-डेकर फ्लाईओवर बन रहा है।यह दिल्ली का पहला पहला डबलडेकर फ्लाईओवर होगा, जिसमें ऊपर के भाग में मेट्रो गुजरेगी, नीचे के भाग में वाहन और इसके नीचे यानी सड़के भाग में भी यातायात जारी रहेगा। इस योजना का 98 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो चुका है। इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद आसपास के क्षेत्र की जनता को लंबे यातायात जाम से नहीं जूझना पड़ेगा और उनका कीमती समय बचेगा।

कश्मीरी गेट आईएसबीटी के बाहर अब नहीं लगेगा जाम, दिल्ली सरकार जल्द करेगी नए नियम की घोषणा; एनजी ने दी हरी झंडी

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 31 अगस्त को कश्मीरी गेट पर महाराणा प्रताप आईएसबीटी का निरीक्षण किया और उसके बाद एक उच्च स्तरीय बैठक की जिसमें दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने भी हिस्सा लिया। परिवहन विभाग दिल्ली के बस अड्डों से अंतरराज्यीय बसों के लिए नई दरों और नियमों को अधिसूचित करने के लिए तैयार है। जल्द ही सरकार इसकी घोषणा करेगी।

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार जल्द ही अंतरराज्यीय टर्मिनलों पर बसों के लिए नई दरें और नियम की अधिसूचना जारी करेगी। राज निवास के अधिकारियों ने रविवार को इसकी जानकारी दी। बता दें, वर्तमान में अंतरराज्यीय बस के लिए न्यूनतम टर्न अराउंड (ठहराव) समय 45-60 मिनट है, जिस कारण बसें आइएसबीटी के बाहर आसपास की सड़कों पर रुक जाती हैं, जिसके चलते ट्रैफिक जाम हो जाता है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 31 अगस्त को कश्मीरी गेट पर महाराणा प्रताप आईएसबीटी का निरीक्षण किया और उसके बाद एक उच्च स्तरीय बैठक की जिसमें दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने भी हिस्सा लिया। परिवहन विभाग दिल्ली के बस अड्डों से अंतरराज्यीय बसों के लिए नई दरों और नियमों को अधिसूचित करने के लिए तैयार है। दिल्ली में कश्मीरी गेट, आनंद विहार और सराय काले खां में तीन अंतरराज्यीय बस टर्मिनल हैं।

बिना फास्टैग वाले वाहनों की नहीं होगी एंट्री : राज निवास के एक अधिकारी ने कहा, ₹उपराज्यपाल ने सरकारी और निजी बसों के लिए समान पार्किंग दरों और पार्किंग टाइम को समान रूप से कम करने का सुझाव दिया।₹ उपराज्यपाल ने यह भी निर्देश दिया कि ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए केवल फास्टैग वाली बसों को ही टर्मिनल में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए।

उन्होंने कहा, "नई योजना के अनुसार, निजी और सरकारी अंतरराज्यीय बसों को आईएसबीटी पर बस बे का उपयोग करने और समान पार्किंग शुल्क का भुगतान करना होगा। अभी तक निजी बसों में अधिक किराया वसूला जाता है। उन्होंने कहा कि इससे ऐसी स्थिति पैदा होती है, जहां उन्हें आईएसबीटी परिसरों के बाहर सड़कों पर पार्क किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप भारी ट्रैफिक जाम होता है।

दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाने में सबसे अधिक सहयोगी आटो चालको को भी दिया धोखा, फिर भी आटो चालक है चुप, आखिर क्यों ?

संजय बाटला

दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सत्ता सुख प्राप्त करवाने के लिए सबसे प्रबल सहयोगी और मेहनती कार्यकर्ता रहे थे आटो चालक। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बनवाने के बाद उनसे अधिक खुश शायद ही और कोई हुआ हो पर इस सरकार ने उन्हें भी अपने चक्रव्यू में फसा कर नही बक्शा। जी हां यह बहुत बड़ा सत्य है जो सभी जानते हैं पर फिर भी कुछ खुल कर बोल नही पा रहे क्योंकि सरकार तो जो कर रही हैं वह तो गलत है ही पर परिवहन विभाग साथ में जो करके आटो चालको को दिखा रहा है वह उससे भी अधिक गलत है। सरकार भी और परिवहन विभाग के आला अधिकारी आज भी मुंह से तो आटो चालक के हित की बात करते हैं पर अंदर ही अंदर सिर्फ अपने हित के कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। इसके लिए आपको कुछ बाते सपष्ट कर रहा हूं बाकी आप सभी बाते आटो चालक पेश कर ही रहे हैं।

1. दिल्ली में आटो तीन पहिया तीन सवारी रिक्शा का परमिट विभाग के अनुसार एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही मिल सकता है और जिसके नाम पर गलती से भी एक से अधिक परमिट उपलब्ध था उसे अपना परमिट या तो अन्य किसी के नाम पर हस्तांतरित करना होगा या परिवहन विभाग उसे जब्त कर लेगी **मगर दिल्ली सरकार के आदेश पर मेट्रो को हजारों आम जनता के परमिट जारी कर दिए और मेट्रो ने भी सेकडो की गिनती में आगे कंपनियों को दे दिए** अब सवाल यह उठता है की जब एक नाम से एक से ज्यादा आटो का परमिट जारी ही नहीं हो सकता तो उन्हे क्यों जारी किए गए और अगर उन्हें जारी किए गए तो आम जनता एक से ज्यादा परमिट की हकदार क्यो नही ?

2. दिल्ली परिवहन विभाग ने बिना पैनिक बटन जांच शाखा बनाए दिल्ली के व्यवसायिक वाहन मालिकों से कई वर्षो तक उसके नेविगेशन के नाम पर फीस बटोरी और 2021 मे पैनिक बटन सेंटर बनाने के खर्च होने वाला पूरा पैसा भारत सरकार से लेने के बाद भी सेंटर नही बनवाया जो पिछले महीने बार बार महिलाओ की सुरक्षा के प्रति मांग करने पर शुरू किया और विज्ञापनों में अपने नाम की घोषणा कर तारीफ पाई की हमने वाहन मालिकों से लेने वाली फीस माफ कर दी जो भारत सरकार के गैजेट नोटिफिकेशन के अनुसार दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग ले ही नहीं सकता था सेंटर बनाने पर। इसके अलावा अब प्रश्न यह है की जो आदेश विभाग द्वारा इस फीस को माफ) खत्म करने के लिए हुए है वह है जीपीएस ट्रैकिंग के लिए और जो भारत सरकार के पैसों से पैनिक बटन ट्रैकिंग सेंटर बना / शुरू हुआ है उसमे ट्रैकिंग होगी सिर्फ वीएलटीडी सिस्टम की फिर जिन वाहनों में वीएलटीडी संयंत्र नही लगा हुआ क्या उन वाहनों में अब जीपीएस सिस्टम के संयंत्र की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आटो रिक्शा में मीटर जीपीएस सिस्टम के है ना की वीएलटीडी चालित। *यहां सवाल यह है की दिल्ली परिवहन विभाग और दिल्ली सरकार ने आटो चालको के लिए क्यों नहीं बताया उसी आदेश मे की अब चालक सादा मीटर लगा सकता है या जल्द ही विभाग और सरकार उनको नए वीएलटीडी चालित मीटर लगवाने के लिए बाधित करने वाले हैं?

अब आटो चालक और आम जनता स्वयं सोच कर फैसला ले की जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी को सत्ता सुख प्राप्त करवाया यह सरकार उनको भी अपने चक्रव्यू में ले सकती है तो अन्य को कैसे छोड़ सकती हैं।

बुराड़ी के आसपास कई मार्ग बंद, वाहनों के लिए डाइवर्जन भी लागू; पढ़ें पुलिस की एडवाइजरी

परिवहन विशेष न्यूज

बाहरी दिल्ली के बुराड़ी में ट्रैफिक पुलिस ने यातायात के लिए एडवाइजरी जारी की है। बुराड़ी में गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया है जो 17 सितंबर तक चलेगा। इसके चलते वहां भक्तों की भीड़ लगेगी। इसके चलते पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। साथ ही कई मार्गों को बंद किया है और डाइवर्जन भी लागू किया है।

नई दिल्ली। लाल बाग का राजा ट्रस्ट, दिल्ली की ओर से बुराड़ी के निरंकारी समागम के पास गणपति पूजा महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। अभी बाबा बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री महाराज हनुमंत कथा कर रहे हैं, जो 11 सितंबर तक चलेगी। इसके बाद 12 से 17 सितंबर तक आचार्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी श्री राम कथा का पाठ करेंगे। इस महोत्सव के चलते यातायात भी काफी प्रभावित रहेगा। इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है।

इन रास्तों के लिए ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी

अरिहंत मार्ग पर मुकुंदपुर चौक से आजादपुर चौक (दोनों कैरिजवे पर), आउटर रिंग रोड पर बुराड़ी चौक से मुकुंदपुर चौक (दोनों कैरिजवे पर), शांति स्वरूप त्यागी मार्ग से भाई परमानंद मार्ग (बुराड़ी चौक से परमानंद कॉलोनी) पर किसी भी वाहन को रुकने या पार्क करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

डायवर्जन पॉइंट (आवश्यकतानुसार)

योगराज कॉलोनी के पास भाई परमानंद मार्ग पर लाल बत्ती।

आलम बांध रोड (बुराड़ी डीडीए ग्राउंड के सामने)

इन मार्गों पर जाने से बचें

शांति स्वरूप त्यागी मार्ग और भाई परमानंद मार्ग (बुराड़ी चौक से किंग्सवे कैंप चौक तक)

आउटर रिंग रोड (बुराड़ी चौक से मुकुंदपुर चौक कैरिजवे तक)

अरिहंत मार्ग पर मुकुंदपुर चौक से आज़ादपुर चौक तक (दोनों कैरिजवे)

शाह आलम बांध मार्ग

पुलिस की लोगों से अपील

पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वो इन रास्तों से बचकर चलें या बाईपास का प्रयोग करें। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट (सार्वजनिक परिवहन) का प्रयोग करें। ट्रेन, फ्लाइट लेने वाले लोग पर्याप्त समय निकाल कर घर से निकलें। साथ ही लोगों से धैर्य रखने की अपील की है।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

बुराड़ी स्थित डीडीए ग्राउंड में पंडित धीरेंद्र शास्त्री के दिव्य दरबार की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस के करीब तीन हजार जवान तैनात किए गए हैं। बाहरी, उत्तरी-पश्चिमी व बाहरी-उत्तरी इन तीन जिला के पुलिस के जवान चप्पे-चप्पे पर तैनात हैं।

पांच दिवसीय इस दिव्य दरबार की सुरक्षा में 10 पुलिस उपायुक्त व अतिरिक्त उपायुक्त, 30 एसीपी व 107 इंस्पेक्टर भी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस की ओर से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए है, एक कंट्रोल रूम से इन कैमरों की निगरानी रखी

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

रिश्ते को बनाए रखने के लिए कम न करें अपने मानक

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि किसी से प्यार करने का मतलब यह नहीं है कि आपको सिर्फ़ रिश्ता बनाए रखने के लिए अपने मानकों को कम करेंगे। ऐसे कई संकेत हैं, जो संकेत देते हैं कि आप अपने मूल्यों या आत्म-सम्मान से समझौता कर रहे हैं। आइए उनके बारे में जानें, ताकि आप अगली बार के लिए सचेत हो सकें।

जब आप किसी के साथ में आते हैं तो चीजों को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहां-वहां छोटे-मोटे समझौते करने पड़ते हैं। लेकिन ये समझौते, जो पहली नजर में एक छोटी सी समस्या लगते हैं, कभी-कभी जितना दिखते हैं, उससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपका साथी आपके दोस्तों के सामने आपका मज़ाक उड़ाता है या बार-बार आखिरी समय पर योजनाएं रद्द कर देता है, यह पहली नजर में 'कोई बड़ी बात नहीं है' लग सकती है, लेकिन ये व्यवहार समय के साथ हेरफेर, अनादर या इससे भी ज्यादा हानिकारक कुछ और बन सकते हैं।

अगर आप किसी भी तरह से इस तरह के व्यवहार को स्वीकार कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने मानकों को कम कर रहे हैं। दुर्भाग्य से, ये ऐसा कुछ है जो कई लोग करते हैं, वो भी इसे महसूस किए बिना। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि किसी से प्यार करने का मतलब यह नहीं है कि आपको सिर्फ़ रिश्ता बनाए रखने के लिए अपने मानकों को कम करेंगे। ऐसे कई संकेत हैं, जो संकेत देते हैं कि आप अपने मूल्यों या आत्म-सम्मान से समझौता कर रहे हैं। आइए उनके बारे में जानें, ताकि आप अगली बार के लिए सचेत हो सकें।

उनके खराब व्यवहार को ठीक बताना- अपने मानकों को कम करने के सबसे आम संकेतों में से एक है कि आप किसी के द्वारा किए गए गलत या खराब व्यवहार को ठीक बता रहे हैं। 'उसने गलती से कर दिया होगा' या फिर 'मैं ही इसके बारे में ज्यादा सोच रही हूं' सोचना ही अपने मानकों को कम करना है। हर कोई व्यक्ति अपने अच्छे या बुरे दोनों व्यवहार के लिए जवाबदेह है, ऐसे में आपको उनके ओर से उनके खराब व्यवहार को ठीक बताना आपके लिए ठीक नहीं है।

अधूरी जरूरतों को स्वीकार करना- बहुत से लोग ऐसे रिश्तों में बंधकर रहते हैं, जो वास्तव में उन्हें वो संतुष्टि नहीं दे पा रहे या उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिनके वो हकदार हैं। ये भी एक तरीके से अपने मानकों को कम करना है। जिस चीज की आपको जरूरत है और आपका साथी उसे पूरा नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे रिश्ते में रहकर आप खुद के साथ गलत कर रहे हैं।

> “ अगर आप किसी भी तरह से इस तरह के व्यवहार को स्वीकार कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने मानकों को कम कर रहे हैं। दुर्भाग्य से, ये ऐसा कुछ है जो कई लोग करते हैं, वो भी इसे महसूस किए बिना। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि किसी से प्यार करने का मतलब यह नहीं है कि आपको सिर्फ़ रिश्ता बनाए रखने के लिए अपने मानकों को कम करेंगे।

वेट लूज कर रहे हैं तो देसी घी खाएं या नहीं! ज्यादातर लोगों को नहीं पता सच्चाई

इन दिनों कई लोग Weight Loss करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बदलती लाइफस्टाइल और गलत खानपान बढ़ते वजन का कारण बन रहा है। ऐसे में बढ़ते को कंट्रोल करने के लिए लोग कई तरीके अपनाते हैं। Desi Ghee से दूरी बनाना इसमें सबसे आम है। कई लोग इसे को वेट गेन की वजह मानते हैं। डॉक्टर से जानते हैं कि वेट लॉस में घी खाना चाहिए या नहीं।

तेजी से बदलती लाइफस्टाइल इन दिनों लोगों को कई समस्याओं का शिकार बना रही है। मौजूद समय में बढ़ता वजन (Weight gain) कई लोगों के लिए परेशानी वजह बना हुआ है। यह समस्या दुनियाभर में चिंता का विषय बनी हुई है। इतना ही नहीं खुद WHO भी इसे लेकर चेतावनी दे चुका है। मोटापा (Obesity) कई गंभीर समस्याओं की वजह बन सकता है। ऐसे में समय रहते इसे कंट्रोल करना जरूरी है, ताकि इन गंभीर परिणामों से बचा जा सके।

बढ़ते वजन को कंट्रोल करने के लिए लोग कई तरीके अपनाते हैं। डाइटिंग से लेकर एक्सरसाइज तक, लोग अलग-अलग तरीकों की मदद से अपना वजन कम करने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं जब बात Weight Loss की आती है, तो लोग सबसे पहले तेल और घी से दूरी बनाते हैं। कई लोगों का मानना है कि देसी घी (Desi Ghee) खाने से वजन बढ़ता है और यह आपकी वेट लॉस जर्नी को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बारे में काफी कम लोग ही जानते होंगे।

ऐसे में इस बारे सही जानकारी लेने के लिए हमने नोएडा के न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक्स लैब के प्रमुख डॉ.विज्ञान मिश्र से बातचीत की और यह जानने की कोशिश की कि क्या देसी घी में सही में वजन बढ़ाता है और वजन कम करने की कोशिश के दौरान इसे डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए या नहीं। आइए जानते हैं क्या है सच्चाई-

क्या घी से बढ़ता है वजन?

डॉक्टर बताते हैं कि देसी घी, भारतीय घरों में इस्तेमाल होने वाला एक प्रमुख फूड आइटम है। हालांकि, जब बात वेट मैनेजमेंट की बात आती है, तो यह अक्सर चिंता का विषय बन जाता है। हालांकि, घी और वजन बढ़ने के बीच का संबंध जितना लगता है, उससे काफी ज्यादा कम है। घी कैलोरी से भरपूर होता है, जिसमें प्रति चम्मच लगभग 120 कैलोरी होती है, यह ओमेगा-3 और ओमेगा-6 फैटी एसिड जैसे हेल्दी फैट में भी समृद्ध है, जो शरीर के लिए जरूरी होते हैं।

वेट लॉस में मददगार घी!

एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि कम मात्रा में घी खाने से असल में वेट लॉस करने में मदद मिल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि घी पाचन में सुधार और मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसमें मौजूद मीडियम-चेन ट्राइग्लिसराइड्स (एमसीटी) फैट बर्न करने में मदद करने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा घी लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे भूख कंट्रोल होती है और ज्यादा खाने से खुद को रोकने में मदद मिलती है। यही वजह है कि घी रिफाइंड तेल या मक्खन का बेहतर विकल्प है।

सही मात्रा है जरूरी

हालांकि, डॉक्टर ने यह भी बताया कि इसकी मात्रा काफी अहम होती है। आप कितना घी खा रहे हैं, इस पर नियंत्रण रखा जरूरी है। ज्यादा घी खाने से एक्सट्रा कैलोरी इनटेक हो सकता है, जो वजन बढ़ाने में योगदान कर सकता है। ऐसे में एक्सपर्च अपनी डाइट में एक चम्मच घी शामिल करने की सलाह देते हैं। खासकर अगर आप कम कार्ब या केटोजेनिक आहार का पालन कर रहे हैं। इस तरह आप वजन बढ़ने के डर के बिना घी के स्वास्थ्य लाभों का आनंद ले सकते हैं।

गुच्छों में झड़ रहे हैं बाल, तो यहां बताए तरीके से शुरू कर दें मेथी और कढ़ी पत्ते का इस्तेमाल

अनहेल्दी खानपान और खराब लाइफस्टाइल के कारण आज कम उम्र में ही लोग बालों से जुड़ी समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। अगर आप भी इससे छुटकारा पाने के अलग-अलग तरीके अपनाकर थक चुके हैं तो आइए आज आपको मेथी और कढ़ी पत्ते से जुड़ा एक शानदार घरेलू नुस्खा (Hair Care Tips) बताते हैं जिसकी मदद से आप बालों की खोई चमक को भी वापस पा सकते है।

क्या आप जानते हैं कि मेथी और कढ़ी पत्ते का इस्तेमाल बालों से जुड़ी समस्याओं में वरदान साबित हो सकता है? इसमें मौजूद पोषक तत्व न सिर्फ बालों को जड़ से मजबूत बनाते हैं बल्कि झड़ने से भी रोकते हैं। बालों की देखभाल के लिए लोग तरह-तरह के प्रोडक्ट्स और घरेलू नुस्खों को आजमाते हैं, लेकिन मनचाहे नतीजे देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आप भी अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं तो मेथी और कढ़ी पत्ता आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। ये दोनों ही नेचुरल चीजें (Natural Hair Care) बालों को मजबूत बनाने, इन्हें झड़ने से रोकने और नई जड़ों को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। आइए जानते हैं कैसे आप इनका इस्तेमाल करके अपने बालों को हेल्दी और खूबसूरत बना सकते हैं।

मेथी और कढ़ी पत्ते का तेल

मेथी और कढ़ी पत्ते से बना हेयर ऑयल आपके बालों को मजबूत बनाता है और इन्हें झड़ने को रोकता है। इस तेल को बनाना बेहद आसान है और यह पूरी तरह से नेचुरल है।

सामग्री:

नारियल का तेल या जैतून का तेल- 1 कप
मेथी दाने- 2-3 चम्मच
कढ़ी पत्ते- कुछ ताजा पत्तियां

बनाने की विधि:

मेथी और कढ़ी पत्ते का तेल बनाने के लिए सबसे पहले इसे एक कढ़ाई में नारियल या जैतून का तेल गर्म करें।

इसके बाद गर्म तेल में मेथी के दाने और कुछ कढ़ी पत्ते डालें।

फिर इन्हें धीमी आंच पर 10-15 मिनट तक पकाएं।

इसके बाद गैस बंद कर दें और तेल को ठंडा होने दें।

अब इसे छानकर एक कांच की बोतल में भर लें।

यह भी पढ़ें- बेजान त्वचा और झड़ते बालों से पाना है छुटकारा, तो बायोटिन से भरपूर कुछ फूड्स को करें डाइट में शामिल

कैसे करें इस्तेमाल?

इस तेल को हफ्ते में दो बार अपने बालों और स्कैल्प पर लगाएं।

तेल को रात भर लगाकर छोड़ दें और सुबह शैम्पू से हेड वॉश कर लें।

रेगुलर इस्तेमाल से आपको कुछ ही हफ्तों में बालों में अंतर दिखने लगेगा।

मेथी और कढ़ी पत्ते के फायदे

मेथी और कढ़ी पत्ते के इस्तेमाल से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, जिससे बालों का झड़ना कम होता है।

इन चीजों से बने तेल के इस्तेमाल से बालों की ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है और झड़ना कम हो जाता है।

बालों को मुलायम और चमकदार बनाने में भी मेथी और कढ़ी पत्ते से बना तेल काफी फायदेमंद होता है।

आप नारियल तेल या जैतून के तेल के अलावा बादाम का तेल या अरंडी का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

आप इस तेल में आप एलोवेरा जेल या विटामिन ई का कैप्सूल भी मिला सकते हैं।

होलकर की जाति से आने वाले धनगर और सिंधिया के कुनबे वाले आज हैं पिछड़े

पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ

300 वर्ष तक भारत के बड़े भूभाग पर राज करने वाले होलकर की जाति से आने वाले धनगर और सिंधिया के कुनबे वाले आज पिछड़े हैं।

वहीं महाराजा विक्रमादित्य हेमराज तेली के वंशज आज पिछड़े हैं, जिन्होंने अखंड भारत पर राज किया है।

वह मौर्य साम्राज्य आज पिछड़ा/दलित है, जिनके वंशजों ने पीढ़ियों तक बंगाल की खाड़ी से लेकर पर्शिया की सीमा तक अखंड भारतवर्ष पर राज किया। महापद्मनंद और धनानंद का वंशज नाई समुदाय आज पिछड़ा है। जो भारत के सबसे शक्तिशाली राजा होते थे।

हिंदुओं के सबसे पवित्र ग्रंथ रामायण के रचियता महर्षि वाल्मीकि के वंशज आज अछूत कैसे हो गए या हो सकते हैं।

महर्षि वेद व्यास की माता व निषाद समुदाय से आने वाली रानी सत्यवती के वंशज भी आज पिछड़े हैं। जिनके बच्चे हस्तिनापुर पर राज करने वाले कौरव और पांडव अखंड भारत के सबसे महान योद्धा और चक्रवर्ती सम्राट थे।

उस आदिवासी कन्या शकुंतला का समुदाय भी आज अनुसूचित जनजाति में काउंट होता है, जिनके पुत्र ₹भरत₹ के नाम पर इस देश का नाम

भारत पड़ा।

महर्षि वेद व्यास, महर्षि वाल्मीकि, आचार्य विदुर, सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक जैसे और भी अनेका अनेक उदाहरण हैं... जिनके वंशज/स्वजातीय लोग आज स्वयं को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग का बताकर अपने साथ शोषण, दमन और अत्याचार हुआ बताते हैं।

अब सवाल ये उठता है कि...

क्या इतने लंबे समय तक राज करने वाले इन वर्गों के राजाओं ने अपनी ही जात, बिरादरी वालों पर स्वयं ही अत्याचार किया/होने दिया या उन को पढ़ने/बढ़ने नही दिया। उन्हें हजारो वर्षों से अनपढ़, गंवार व शोषित बनाये रखा।

भगवान कृष्ण के वंशज होने का दावा करने वाले, आज भी बड़ी बड़ी जमीन जायदाद वाले खेती किसानी करने वाले हर तरह से संपन्न यदुवंशी अंततः पिछड़े कैसे हो गए।

मध्य काल में बहराइच से नेपाल तक बड़े भूभाग पर राज करने वाले पासी आखिर दलित कैसे हो गए।

मध्यकाल में प्रसिद्ध पाल वंशी राजाओं के वंशज कैसे पिछड़े हो गए।

इतिहास में चंवर वंशी राजाओं का जिक्र है, जो आज दलित कहे जाते हैं।

गौर, गुर्जर, मीणा, जाट, वर्मा, गोंड आदि वर्ग के राजा सब बड़े लम्बे समय तक शासक रहे हैं। देश के इतिहास में इनकी छाप है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मुगल आक्रांताओं के शासन काल व उसके बाद अंग्रेजी शासन काल की गुलामी के बाद ये सारे वर्ग विभाजित होकर वंचित, शोषित और पीड़ित कहलाने लगे... क्या किसी ने यह विचार किया कि कहीं विदेशी आक्रांताओं ने ही हिंदू सनातन समाज में फूट डालने के लिए ये अंकुरण तो नहीं किया ?

परतंत्रता से निकलने के बाद भी विभाजन की दोधारी तलवार से समस्त हिंदु समाज को काटने की रणनीति के चलते ही 1947 के बाद इस विभाजन को और गहरा ही किया गया।

अन्यथा यह कैसे संभव है कि तुम लंबे समय तक राज भी करो और विदेशी नेक्सस के फैलाए जाल में फंसकर विक्टिज़्म भी बन जाओ... और राजा बनने के बाद भी क्या आपके स्वजातीय राजा अपनी जात/बिरादरी के साथ ऐसा ही करते रहे कि वो अनपढ़/गंवार/मूर्ख/पिछड़ा/दबा/कुचला ही बना रहे।

स्वयं को जानों स्वयं को पहचानों स्वयं के करो दीदार

स्मृतियों के जगत में स्वयं के अनुभव से अनुपम उद्दात्त और मधुर अन्य कोई स्मृति नही है। अतः प्रत्येक पल अपनी स्मृति को आधार मान कर स्वयं के साथ एकात्मता अभिन्नता का अनुभव ही आध्यात्मिक मार्ग की सफलता है ! जिसे हम संपत्ति मानते हैं वह संपत्ति नहीं होती और जिसे विपत्ति समझते हैं वह वास्तव में विपत्ति भी नहीं होती। स्वयं का विस्मरण ही मानव की सबसे बड़ी विपत्ति है। स्वयं के भीतर स्वयं का स्मरण ही जीवन में पूर्णता को प्राप्त करना है। जब तक श्वास का सानिध्य प्राणी मात्र के हृदय में समाया हुआ है स्वयं से कोई भी विलग नहीं है ! स्वयं का विस्मरण ही विपत्ति है और स्वयं के स्मरण से बड़ी कोई संपत्ति इस संसार में नहीं। जब दुःख की परिस्तिथि को स्वीकार भाव से स्वीकार करते हैं तो वह सकारात्मकता दिव्य स्मरण से व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक प्रगति के उत्प्रेरक बन जाते हैं। सच्चा साधक वही है जो अपने प्रति सतर्क और सचेत है। जिसने भी सरलता संयम और धैर्य को सहज कर रखा है वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कभी चिन्तित, निरुत्साहित, आशाहीन, दुःखी असमर्थ नहीं होता। वह अपने व्यवहार में किसी व्यक्ति, समाज, राष्ट्र का कोई अहित नहीं करता है। अतः सच्चा भक्त वही है जो तपस्वी, सामर्थ्यवान, निष्काम सेवाभाव, निर्भीक और प्रसन्न रहता है।

हर 10 मिनट के अंतराल पर मिलेगी मेट्रो, ऐप से बुक कर सकेंगे टिकट; कीमत को लेकर सामने आई जानकारी

मेरठ में मेरठ मेट्रो का कॉरिडोर 23 किलोमीटर लंबा है। इसमें 18 किलोमीटर का कॉरिडोर एलिवेटेड और पांच किलोमीटर भूमिगत खंड शामिल हैं। 13 स्टेशन में से नौ स्टेशन एलिवेटेड तीन भूमिगत और एक स्टेशन धरातल पर होगा। मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण कार्य तेज गति से किया जा रहा है। 18 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड सेक्शन में से मेरठ साउथ से मोदीपुरम स्टेशन तक वायडक्ट का निर्माण लगभग पूरा है

गाजियाबाद। नमो भारत ट्रेन का परिचालन शुरू करने के बाद एनसीआरटीसी द्वारा अब मेट्रो का परिचालन मेरठ में करने के लिए तैयारी तेज कर दी गई है। मेरठ में 23 किलोमीटर के क्षेत्र में 13 स्टेशन के बीच चलने वाली मेट्रो प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगी।

शुरूआत में यात्रियों के लिए 10 मेट्रो ट्रेन मेरठ में चलाने की तैयारी की गई है। वर्तमान में जिस तरह से नमो भारत ट्रेन में सफर करने वाले यात्री आरआरटीएस के ऐप, क्यूआर कोड और ऑफलाइन माध्यम से टिकट लेते हैं, उसी तरह मेट्रो में सफर के लिए भी टिकट बुक कर सकेंगे।

मेरठ मेट्रो का कॉरिडोर 23 किलोमीटर लंबा

मेरठ में मेरठ मेट्रो का कॉरिडोर 23 किलोमीटर लंबा है। इसमें 18 किलोमीटर का कॉरिडोर एलिवेटेड और पांच किलोमीटर भूमिगत खंड शामिल हैं। 13 स्टेशन में से नौ स्टेशन एलिवेटेड, तीन भूमिगत और एक स्टेशन धरातल पर होगा। मेरठ मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण कार्य तेज गति से किया जा रहा है। 18 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड सेक्शन में से मेरठ साउथ से मोदीपुरम स्टेशन तक वायडक्ट का निर्माण लगभग पूरा हो गया है और भूमिगत सुरंग का निर्माण कार्य भी पूरा हो गया है।

दिसंबर के अंत तक काम हो जाएगा पूरा

मेरठ मेट्रो के सभी स्टेशनों ने आकार लेना भी शुरू कर दिया है। भूमिगत स्टेशनों की फिनिशिंग का कार्य किया जा रहा है। दुहाई डिपो में मेरठ मेट्रो की टेस्टिंग का कार्य किया जा रहा है। 23 किलोमीटर लंबा पूरा कॉरिडोर का कार्य दिसंबर के अंत में पूरा होने की उम्मीद है, इसके बाद मेरठ में ट्रैक पर ट्रायल रन के लिए मेरठ मेट्रो दौड़ती हुई नजर आएगी। जून 2025 से मेट्रो का परिचालन मेरठ में यात्रियों के लिए करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

टिकट की कीमत को लेकर अधिकारी ने बताया

दिल्ली मेट्रो से अधिक सुविधाओं वाली मेरठ मेट्रो में टिकट के दाम उससे अधिक होंगे या फिर कम होंगे। इसको लेकर भी मेट्रो के अनावरण के कार्यक्रम के बाद चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि ट्रेन के दाम क्या होंगे, इस पर एनसीआरटीसी के एक अधिकारी ने बताया कि टिकट के दाम को लेकर मंथन किया जा रहा है। अब तक टिकट के दाम तय नहीं किए गए हैं।

श्री धार्मिक लीला कमेटी के भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष

सुषमा रानी

नई दिल्ली, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव आज श्री धार्मिक लीला कमेटी के भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए और वहां भगवान श्रीराम का आर्शीवाद लिया। श्री धार्मिक लीला कमेटी द्वारा रामलीला का आयोजन माधवदास पार्क, लाल किला मैदान, पुरानी लाजपत राय मार्केट के सामने किया जाता है, वहां भूमि पूजन विधि विधान से सम्पन्न हुआ। भूमि पूजन के कार्यक्रम में श्री धार्मिक लीला कमेटी के पदाधिकारियों के अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव, दिल्ली कांग्रेस कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज, धार्मिक लीला कमेटी के महामंत्री धीरज धर गुप्ता, पूर्व विधायक कुवंर करण सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष मौहम्मद उस्मान, पूर्व पार्षद अशोक जैन, दिल्ली सोशल मीडिया चेयरमैन राहुल शर्मा भी मौजूद थे।

भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनो दिल्ली वालों को सस्ती प्याज देने में विफल : देवेन्द्र यादव

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि राजधानी में सब्जियों के दामों में अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी पर नियंत्रण करने में केजरीवाल की दिल्ली सरकार चौतरफा विफल रही है। नेतृत्वहीन दिल्ली सरकार की निर्षक्रियता के कारण दिल्लीवासी को रोजमर्रा की रसाई में जरुरत प्याज 70-75 रुपये तक जनता की पहुॅच से बाहर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अप्रत्याशित महंगाई पर कभी बात न करने वाली भाजपा और आप पार्टी की जनता के प्रति दोहरी नीति के कारण पिछले 10 वर्षों में रसोई का बजट चौगुना पहुॅच गया है।

देवेन्द्र यादव ने कहा कि अपनी उलझनों में उलझी आम आदमी पार्टी ने कभी जनता की परेशानियों को समझा ही नही। दिल्ली में प्याज 75 रुपये, टमाटर 80 रुपये, लहसन 240 रुपये, अदरक 200 रुपये, गोबी 160 रुपये के अलावा कोई भी हरी सब्जी 60-80 रुपये से कम नही है, जबकि हर काम आने वाला आलू भी लोकसभा चुनाव से अभी तक 40 रुपये से कम नही हुआ है, जो कांग्रेस के समय कभी 15 रुपये अधिक नही पहुॅचा। दिल्ली की जनता मानसून की मार के साथ-साथ आम आदमी पार्टी और भाजपा की आपसी लड़ाई का खामियाजा भुगत रही है।

उन्होंने कहा कि भाजपा नेता केन्द्र सरकार की एजेंसी नेफेड द्वारा प्याज 35 रुपये प्रति किलो देने का दावा कर रही है परंतु नेफेड की गाड़ियों को गरीब बस्तियों और जरुरतमंद लोगों तक पहुॅचाने की व्यवस्था नही करती? भाजपा जवाब दें कि दिल्ली की जनसंख्या के अनुपात में राजधानी में नेफेड कितनी वेनों में प्रतिदिन प्याज जनता को उपलब्ध करा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता को तिगुनें दामों में प्याज मिलने में भाजपा भी बराबर की जिम्मेदार है। जब आजादपुर मंडी में 35-45 रुपये किलो प्याज पहुंच रहा है, तो जनता तक पहुंचने में दुगने दाम में कैसे मिल रहा है। दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग की सब्जी विक्रेताओं से कोई सांठगांठ है, जो निरंकुशता के साथ सब्जियों के दामों में वृद्धि हो रही है।

उन्होंने कहा कि लम्बे समय से दिल्ली जनता अपनी आंखों से भाजपा और आम आदमी पार्टी का सड़कों पर नंगा नाच देख रही है कि कैसे वो अपने राजनीति फायदे के लिए जनता से जुड़े मुद्दों, मूलभूत सुविधाओं और दैनिक परेशानियों का निपटाने में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे है।

देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली में 40 हजार राशन कार्ड निरस्त करना दिल्ली की गरीब जनता पर सीधा हमला है। एक तरफ दिल्ली में 11 लाख राशन कार्ड के आवेदन पेंडिग पड़े है और दूसरी तरफ दिल्ली के खाद्य आपूर्ति मंत्री 40 हजार राशन कार्ड निरस्त कर रहे है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के खाद्य मंत्री राजधानी में प्याज के दामों साहित सब्जियों के दामों को नियंत्रित करने पर ध्यान दें। यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता ''आपका विधायक आपके द्वार के अंतर्गत जनता से मिलकर उनकी परेशानियों, महंगाई पर नियंत्रण करने और उन्हें मूलभूत सुविधाएं देने की बजाय फिर एक बार उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे है।

खादू श्याम जागरण में श्रद्धालुओं की सेंट जोहन एम्बुलेंस ब्रिगेड ने की सेवा

परिवहन विशेष दिल्लीः दिल्ली के हरकेश नगर ओखला में श्री खाटू श्याम सेवा मण्डल द्वारा 07 सितंबर 2024 जागरण का आयोजन किया गया। जिसमें सेन्ट जोहन एम्बुलेंस ब्रिगेड की दक्षिण पुर्वी दिल्ली की टीम के कोर्प्स ऑफिसर श्री श्याम कुमार के नेतृत्व में डिविजन कमांडर श्री दिलीप कुमार एम्बुलेंस ऑफिसर श्री प्रदीप कुमार एवं सार्जेंट श्री प्रेम चंद ने कुल आठ सदस्यों के साथ जागरण में आये श्रद्धालुओं की सेवा की। जागरण के दौरान कुछ भक्तों को हाथ पैर में मामूली चोटें लगी जिनपर पट्टी कर भक्तों को घर भेज दिया गया।

सेन्ट जोहन एम्बुलेंस ब्रिगेड के इस सहयोग के लिये मण्डल अध्यक्ष श्री उदीन कुमार जी ने काफी सराहना की और धन्यवाद दिया। जागरण में क्षेत्र के पुर्व सांसद श्री रमेश विधुड़ी जी ने भी फ़र्स्ट एड पोस्ट पर आकर कोर्प्स ऑफिसर श्री श्याम कुमार से मुलाकात की व ब्रिगेड के कार्य को भी सराहा। जागरण के उपरांत मण्डल अधिकारियों सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया।

जन्माष्टमी पर सेन्ट जोहन एम्बुलेंस ब्रिगेड के करीब 100 स्वयंसेवक व 10 अधिकारियों ने फ़र्स्ट एड पोस्ट लगाकर मन्दिर में आये श्रद्धालुओं की सेवा की

पीडी वर्खिया

नई दिल्ली। दक्षिण पुर्वी दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलास में स्तिथ इस्कॉन मंदिर में वर्ष 2024 में जन्माष्टमी के दौरान सेन्ट जोहन एम्बुलेंस ब्रिगेड के करीब 100 स्वयंसेवक व 10 अधिकारियों ने श्रीमती मोनिका जी कोर्प्स ऑफिसर के नेतृत्व में कुल ग्यारह फ़र्स्ट एड पोस्ट लगाकर मन्दिर में आये श्रद्धालुओं की सेवा की।

यह सेवा जन्माष्टमी के दिन सुबह 06.00 बजे शुरू होकर रात्रि 12.30 बजे समाप्त हुई इस दौरान करीब एक लाख से अधिक श्रद्धालु मन्दिर में दर्शन करने आये इस दौरान कुल 350 श्रद्धालुओं को मल्हम पट्टी व जुकाम खांसी व उल्टी आदि में दवा देकर सहायता दी गई। एक सिरियस कैज्युल्टी को कैट्स एम्बुलेंस द्वारा सफदरजंग अस्पताल भेजा गया।

अधिकारियों के नाम जिन्होंने सुबह 06.00 बजे से रात्रि 12.30 बजे तक अपनी सेवाएं प्रदान कीं उनके नाम व पद निम्लिखितानुसार हैं।

1) Ms Monika C.O.
2) Ms Tannu Div. Cdr. N
3) Sh Chandan A.O.
4) Sh Yogendra Kumar A.O.
5) Ms jyoti Sgt. N
6) Sh Yash Sgt
7) Sh Vijay Kumar Mahto Sgt
8) Sh Prem Chaudhari Sgt
9) Ms Vishakha Corpolar
10) Sh Sumit Kumar Member

सेन्ट जोहन एम्बुलेंस ब्रिगेड की सहायता कैट्स एम्बुलेंस की ओर से कुल 06 एम्बुलेंस देकर की।

पेमेंट गेटवे के छोटे ट्रांजेक्शन पर जीएसटी लगाने से लाखों स्टार्ट-अप्स और छोटे बिज़नेस को होगा नुक़सान

सुषमा रानी

नई दिल्ली। 54वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में केजरीवाल सरकार 2000 रुपये से कम के पेमेंट गेटवे ट्रांजेक्शन पर जीएसटी का विरोध करेगी। इस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए साझा करते हुए वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि, भाजपा शासित केंद्र सरकार ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से 2000 रुपये तक के पेमेंट पर भी जीएसटी लगाने का प्रस्ताव ला रही है।

उन्होंने कहा कि, पेमेंट गेटवे के छोटे ट्रांजेक्शन पर जीएसटी लगाने से लाखों स्टार्ट-अप्स और छोटे बिज़नेस को नुक़सान होगा।

वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि, अभी तक 2000 रुपये से कम के ऑनलाइन पेमेंट पर जीएसटी नहीं लगता था लेकिन अब केंद्र सरकार पेमेंट गेटवे पर होने वाले सभी पेमेंट पर 18% जीएसटी लगाने की तैयारी में है। यदि पेमेंट गेटवे पर जीएसटी लगता है तो इसका सीधा असर लाखों छोटे बिज़नेस और स्टार्ट-अप्स पर पड़ेगा।

वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि, देश के लाखों स्टार्टअप्स के हित में केजरीवाल सरकार कल व्यापार विरोधी इस प्रस्ताव का जीएसटी काउंसिल बैठक में पुरज़ोर विरोध करेगी।

वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि, भाजपा शासित केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने भाषणों में कहते आये है कि वो डिजिटल पेमेंट को, कैशलेश इकॉनमी को बढ़ावा दे रहे है लेकिन भाजपा का दोगलापन ये है कि, कल जीएसटी काउंसिल में केंद्र सरकार ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से 2000 रुपये तक के पेमेंट पर जीएसटी लगाने का प्रस्ताव ला रही है। अभी तक ये जीएसटी के दायरे से बाहर थे।

उन्होंने कहा कि, अभी तक कोई व्यक्ति यदि ऑनलाइन कोई सामान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम ख़रीदते है और यदि भुगतान की राशि 2000 रुपये या इससे कम होती है तो उसपर जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन केंद्र सरकार कल जीएसटी काउंसिल के माध्यम से प्रस्ताव लेकर आ रही है कि जो भी भुगतान ऑनलाइन माध्यम से होते है चाहे वो 2000 रुपये से कम हो लेकिन उन्हें भी जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा।

वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि, ऑनलाइन ख़रीददारी के दौरान किए जाने वाले भुगतान विभिन्न पेमेंट गेटवे के माध्यम से होते है। अभी तक यदि ये पेमेंट 2000 रुपये से कम की होती थी तो उनपर जीएसटी नहीं लगता था लेकिन अब केंद्र सरकार अब पेमेंट गेटवे पर होने वाले सभी पेमेंट चाहे वो 2000 से कम हो या ज़्यादा हो उसपर 18% जीएसटी लगाने की तैयारी में है।

उन्होंने कहा कि, ऐसे में यदि इन पेमेंट गेटवे पर जीएसटी लगता है तो ज़ाहिर तौर पर ये कंपनियों इसका भुगतान उपभोक्ताओं से लेंगी। इसका सीधा असर छोटे बिज़नेस और स्टार्ट-अप्स पर पड़ेगा। आज बहुत से बिज़नेस इंस्टाग्राम और छोटे वेबसाइटों के माध्यम से चल रहे है। ये सभी लेनदेन के लिए पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते है। तो अगर पेमेंट गेटवे पर जीएसटी लगा तो इसका सबसे ज़्यादा असर छोटे बिज़नेस पर पड़ेगा।

उन्होने कहा कि, भारत का 30% जीडीपी और 62% रोजगार छोटे बिज़नेस से आता है। ऐसे में जहां सरकार को छोटे बिज़नेस को बढ़ावा देना चाहिए, टैक्स में छूट देनी चाहिए उसकी बजाय केंद्र सरकार पेमेंट गेटवे पर टैक्स लगाकर उनपर बुरा प्रभाव डालेगी। इसलिए 2000 रुपये से कम के ट्रांजेक्शन पर जीएसटी लगाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार ला रही है, कल दिल्ली सरकार इसका जीएसटी काउंसिल की बैठक में पुरज़ोर विरोध करेगी।

ट्रैवल कंपनी खोल दुबई-कुवैत में नौकरी का दिया झांसा, 250 लोगों से पैसे लेकर हो गए फरार

परिवहन विशेष न्यूज

ठगों ने ट्रैवल कंपनी खोलकर लोगों को विदेशों में नौकरी का झांसा दिया। उन्होंने नौकरी को लेकर सभी तरह की प्रक्रिया कर लीं। जब फ्लाइट उड़ाने भरने को थी उससे एक दिन पहले शातिर लोगों के मोबाइल पर मैसेज भेजकर फरार हो गए। बिहार यूपी कर्नाटक समेत देशभर के पीड़ितों ने सेक्टर-63 थाने पहुंचकर शिकायत की।

दुबई, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान समेत आयरलैंड, लक्जमबर्ग, मालदीप में नौकरी के नाम पर 250 से ज्यादा लोगों से 1.75 करोड़ रुपये की ठगी कर ली। ठग सेक्टर-63 में ग्लोबल ट्रैवल्स नाम से कार्यालय चलाकर देशभर से लोगों को जोड़ रहे थे। फर्जी फ्लाइट के उड़ान भरने से एक दिन पहले ही आरोपी कार्यालय बंद कर भाग गए। आरोपियों ने पांच माह पहले कार्यालय किराये पर लिया था। पीड़ितों ने थाने में शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है।

फेसबुक से मिली नौकरी की जानकारी

पीड़ित दिनेश कुमार, अल्ताफ, अरमान ने सेक्टर-63 थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि तीन माह पहले फेसबुक पर विदेश में नौकरी की वैकेंसी होने की जानकारी मिली थी। भारतीय व नेपाली कामगारों को कसाई, मीट पैकर, चिलर, सुपरवाइजर आदि पद पर भेजा जाना था।

विदेश भेजने की प्रक्रिया कराई

जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक करने से ग्लोबल ट्रैवल्स कंपनी के ग्रुप से जुड़ गए। कंपनी स्टाफ ने 15 दिन में वीजा मिलने की जानकारी देना बताया। इसके एवज में फीस के नाम पर रुपये लिये और आवेदन करा लिया। स्टाफ ने दस्तावेज लेकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कराई और छह सितंबर का फ्लाई टिकट दिया गया।

जाने से एक दिन पहले मैसेज ने चौंकाया

एक दिन पहले ग्रुप पर मैसेज आया कि टिकट कैंसल हो गया है और किसी को एयरपोर्ट नहीं जाना है। बिहार, कर्नाटक, यूपी से पहुंचे लोग कंपनी कार्यालय पहुंचे तो गेट बंद मिला। पीड़ितों ने स्टाफ के नंबर पर कॉल किया तो फोन नंबर बंद आए। इससे पीड़ितों को अपने साथ ठगी होने का एहसास हुआ।

यह था सैलरी स्लेव व पद

कसाई- 2200 दिरहज
चिलर ऑपरेटर- 2500 दिरहम
मीट पैकर- 1700 दिरहम
काउंटर ब्वॉय- 1800 दिरहम
क्लीनर- 1400 दिरहम
सुपरवाइजर- 3000 दिरहम
डिलीवरी ब्वॉय- 1900 दिरहम

इन लोगों से हुई ठगी

प्रदीप पुरी व शहवाज आलम से आठ-आठ लोगों के एवज में 6.40 लाख, विकास से 80 हजार, दिनेश कुमार से 65 हजार, सुरेश कुमार से 65 हजार, अजय गिरि से 80 हजार, धर्मेश से 1.20 लाख, जसवेंद्र से 60 हजार, संदीप से 65 हजार, सुनील से 65 हजार, मनीष से 65 हजार, राजपाल से 65 हजार, महेश से 65 हजार, यूसूफ से 56 हजार रुपये, तुफैल से 3.20 लाख रुपये, मुलायम यादव से 2.70 लाख रुपये, मंटू व मनीष कुमार से 90-90 हजार रुपये लिए गए। इन लोगों ने अपने साथ 46 लोगों से इस तरह की ठगी होने के साक्ष्य दिये हैं।

35 हजार रुपये किराये पर लिया था कार्यालय

पीड़ित शहवाज आलम ने बताया कि आरोपियों ने सेक्टर-63 के एच ब्लाक में कार्यालय के लिए फ्लैट 35 हजार रुपये किराये पर लिया था। 11 माह का रेंट एग्रीमेंट किया हुआ है। 70 हजार रुपये एडवांस के रूप में जमा भी किये थे। रेंट एग्रीमेंट नमिता सबरवाल और जोनी दास के बीच होने के दस्तावेज मिले हैं। एग्रीमेंट करने वाले का नाम और फ्लैट मालिक की जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराई गई है।

डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्तिमोहन अवस्थी ने बताया कि शिकायत के आधार पर जांच कराकर कार्रवाई की जा रही है।

खुशखबरी: अब 55 की जगह डॉक्टरों को मिलेगा 80 हजार वेतन, इसी महीने इंटरव्यू के जरिए होगी नियुक्ति

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए शासन स्तर से बड़ा फैसला लिया गया है। अब कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टरों को 55 हजार की जगह 80 हजार रुपये मासिक वेतन मिलेगा। इसके अलावा उन्हें 20 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इस कदम से नौकरी छोड़ रहे डॉक्टरों को रोका जा सकेगा और अस्पतालों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी।

गाजियाबाद। गाजियाबाद के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित स्वास्थ्य केंद्र, यूपीएचसी, सीएचसी और जिला अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने के साथ ही चिकित्सकों की कमी दूर करने की तैयारी तेज हो गई है।

20 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी

शासन स्तर से जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से नियुक्त किये जाने वाले चिकित्सकों को अब 55 की जगह 80 हजार रुपये का मासिक वेतन मिलेगा। इसके अलावा 20 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि भी हर माह मिलेगी। इसके साथ ही कम वेतन और अधिक कार्य के चलते नौकरी छोड़ रहे चिकित्सकों को रोका जा सकेगा।

अस्पतालों में हैं डॉक्टरों की कमी

इसी महीने साक्षात्कार के माध्यम से चिकित्सकों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रस्तावित है। 17 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सक नहीं हैं। कई सीएचसी पर चिकित्सकों की कमी है। जिला अस्पतालों में भी विशेषज्ञों की कमी चल रही है।

जिले में एक साल से हृदयरोग विशेषज्ञ नहीं है। एनएचएम के तहत मेडिकल संसाधन बढ़ाने, स्टाफ और स्वास्थ्य योजनाओं का डिजिटलीकरण करने पर फोकस किया जा रहा है।

अस्पतालों में तैनात चिकित्सकों का पूरा विवरण

अस्पताल	कुल चिकित्सक
जिला संयुक्त अस्पताल	27
जिला महिला अस्पताल	9
जिला एमएमजी अस्पताल	23
सीएचसी मुरादनगर	11
संयुक्त अस्पताल लोनी	9
सीएचसी लोनी	19
सीएचसी मोदीनगर	5
पीएचसी भोजपुर	11
सीएचसी बम्हैटा	4
सीएचसी डासना	5
शहरी (पीएचसी)	36
शहरी (एचडब्ल्यू सी)	56

जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से साक्षात्कार के आधार पर चिकित्सकों की नियुक्ति को लेकर शासन स्तर से वेतनमान में वृद्धि कर दी है। पहले 55 हजार और 20 हजार प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। नई स्वीकृति के तहत 80 हजार वेतन और 20 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि प्रतिमाह दी जाएगी। इसके साथ ही चिकित्सकों की कमी पूरी की जा सकेगी। इसी महीने साक्षात्कार होंगे। कई नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य कल्याण केंद्र(हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर) पर चिकित्सकों की तैनाती नहीं हो रही है। नई नियुक्ति प्रक्रिया के बाद केंद्रों को प्रभारी मिल सकेंगे। - डॉ. अखिलेश मोहन, सीएमओ

गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा: बस ने स्कूटी में मारी टक्कर, दो लोगों की मौत

गाजियाबाद में रविवार सुबह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां न्यू लिंक रोड पर बस ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूटी सवार दोनों की जान चली गई। हादसे के वक्त स्कूटी सवार दिल्ली से मेरठ तिराहे की तरफ जा रहे थे। पीछे बैठे युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।

गाजियाबाद। न्यू लिंक रोड पर सुबह तेज रफ्तार बस ने स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार दोनों सवारी की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक त्रिलोकपुरी दिल्ली निवासी सुशील कुमार दिल्ली से मेरठ तिराहे की तरफ जा रहे थे। उनके साथ एक सवारी और बैठी हुई थी।

पुलिस का कहना है कि सुबह करीब आठ बजे न्यू लिंक रोड पर एनएच-नौ से मेरठ तिराहे की तरफ मुड़ने के कुछ ही दूर बाद पीछे से बस ने स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार सुशील की अस्पताल ले जाते हुए मौत हो गई जबकि दूसरी सवारी की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस का कहना है कि पीछे बैठे युवक की पहचान नहीं हो पाई है।

मसूरी में ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, मौत

उधर, एक अन्य हादसे में एनएच-नौ पर मसूरी थानाक्षेत्र में शुक्रवार रात तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चला रहे उमर फारुख की मौत हो गयी जबकि उनका भतीजा सात वर्षीय उजैक घायल हुआ है।

डासना के दूधिया पीपल निवासी मारूफ के मुताबिक शुक्रवार रात उनके पिता उमर फारुख (55 वर्ष) बाइक पर भतीजे उजैक को लेकर डासना से मसूरी की तरफ जा रहे थे। मसूरी रेलवे रोड कट के पास उनकी बाइक में पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। घटना के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। उन्हें पुलिस ने घटना की जानकारी दी।

सुपरटेक के 17 प्रोजेक्ट को तीन फेज में पूरा करने का प्रस्ताव, सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी फाइनल मंजूरी

परिवहन विशेष न्यूज

सुपरटेक की 17 अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एनबीसीसी ने तीन चरणों का प्रस्ताव दिया है। पहले चरण में नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सात परियोजनाएं शामिल हैं। दूसरे चरण में नोएडा ग्रेटर नोएडा और मेरठ की पांच परियोजनाएं हैं। तीसरे चरण में गुरुग्राम और उत्तराखंड की परियोजनाएं शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट से एनबीसीसी द्वारा दिए गए फाइनल प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी।

ग्रेटर नोएडा। सुपरटेक की अधूरी 17 परियोजनाओं को तीन फेज में पूरा करने के लिए प्रस्ताव बनाकर नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी (एनबीसीसी) ने दिया है। प्रस्ताव पर फाइनल मंजूरी सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी। यह अधूरे प्रोजेक्ट नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, मेरठ और उत्तराखंड में हैं। बिल्डर के दिवालिया घोषित होने से यह मामला अब कोर्ट के अधीन हैं।

घर मिलने की राह देख रहे 15 हजार से ज्यादा खरीदार

बता दें सुपरटेक की अलग-अलग परियोजनाओं में 15 हजार से ज्यादा खरीदार घर मिलने की राह देख रहे हैं। बिल्डर ने समय पर परियोजनाओं को पूरा नहीं किया। एक दशक से अधिक समय में लोगों को बुक किए घर नहीं मिल सके।

बिल्डर दिवालिया घोषित हो चुका है। परियोजनाओं में निर्माण कार्य बंद है। मामला अदालत में विचाराधीन है। एनबीसीसी ने सुपरटेक की अधूरी परियोजनाओं को तीन फेज में पूरा करने का प्रस्ताव दिया है।

पहले फेज में नोएडा की रोमानो, केपटाउन, इकोसिटी और ग्रेटर नोएडा की इकोविलेज-दो, सीजार, इकोविलेज-तीन, स्पोर्ट्स विलेज समेत सात परियोजनाओं को शामिल किया गया है।

दूसरे फेज में किसे किया गया शामिल?

दूसरे फेज में नोएडा की नार्थआई, ग्रेटर नोएडा की अपकंट्री, इकोविलेज-एक और मेरठ की मेरठ स्पोर्ट्स सिटी, ग्रीन विलेज मेरठ को शामिल किया गया है। तीसरे फेज में गुरुग्राम की हलटाउन, अराविले, उत्तराखंड की रिवरक्रस्ट, दून स्क्वायर और बैंगलौर की मिकासा को शामिल किया है।

सुप्रीम कोर्ट से एनबीसीसी द्वारा दिए गए फाइनल प्रस्ताव की मंजूरी मिलेगी।

अखिलेश का हरियाणा में समर्थन, क्या कांग्रेस यूपी उपचुनाव और भविष्य में वैसा ही सहयोग

अजय कुमार

अखिलेश यादव ने हाल ही में हरियाणा विधानसभा चुनाव से अपनी पार्टी के कदम पीछे खींचने की घोषणा की। यह निर्णय तब आया जब कांग्रेस ने सपा को हरियाणा में अधिक सीटें देने से इंकार कर दिया। कांग्रेस की इस स्थिति ने अखिलेश यादव को एक नई रणनीति अपनाने पर मजबूर किया।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव का हरियाणा विधानसभा चुनाव से पीछे हटना और कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला राजनीति के खेल में एक बड़ा बदलाव लाया है। यह कदम न केवल हरियाणा की राजनीति को प्रभावित करेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी इसके गहरे प्रभाव हो सकते हैं। अखिलेश यादव ने इस निर्णय के साथ एक महत्वपूर्ण संकेत दिया है कि सपा की प्राथमिकता बीजेपी को हराने की है, न कि अपने राजनीतिक हितों की रक्षा करना।

अखिलेश यादव ने हाल ही में हरियाणा विधानसभा चुनाव से अपनी पार्टी के कदम पीछे खींचने की घोषणा की। यह निर्णय तब आया जब कांग्रेस ने सपा को हरियाणा में अधिक सीटें देने से इंकार कर दिया। कांग्रेस की इस स्थिति ने अखिलेश यादव को एक नई रणनीति अपनाने पर मजबूर किया। अखिलेश ने स्पष्ट किया कि सपा की प्राथमिकता बीजेपी को हराना है और इसके लिए वे हर त्याग करने को तैयार हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि यह समय अपने राजनीतिक लाभ की सोचने का नहीं, बल्कि जनता के दुख-दर्द को समझने और बीजेपी की सियासत से उन्हें मुक्ति दिलाने का है।

सपा ने हरियाणा चुनाव के लिए 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई थी। पार्टी की प्रदेश इकाई ने जुलाना, सोहना, बावल, बेरी, चरखी-दादरी, और बल्लभगढ़ जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अपनी नजर गड़ी थी। लेकिन जब कांग्रेस ने सपा को एक सीट से ज्यादा देने से मना कर दिया, तो अखिलेश ने इस स्थिति का सामना करते हुए हरियाणा चुनाव से अपने कदम पीछे खींचने का निर्णय लिया। इस फैसले के साथ उन्होंने कांग्रेस को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है, जिससे उनकी पार्टी की इस चुनावी लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना बनी है।

अखिलेश यादव का यह त्याग कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती और एक मौका दोनों है। यदि कांग्रेस यूपी और महाराष्ट्र में सपा की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती, तो इसका असर दोनों दलों के रिश्तों पर पड़ सकता है। अखिलेश का हरियाणा में दिया गया समर्थन कांग्रेस को एक ऐसा मौका प्रदान करता है जिससे वह बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बना सके। लेकिन इसके बदले में कांग्रेस को यह साबित करना होगा कि वह सपा की उम्मीदों पर खरी उतर सकती है।

उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस बार उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि उनकी पार्टी इन उपचुनावों में 10 में से 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह घोषणा कांग्रेस की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाती है, लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि कांग्रेस को उपचुनाव में केवल एक या दो सीटें ही मिलेंगी। उनकी पार्टी की रणनीति मौजूदा पांच सीटों को बचाए रखने और एनडीए की पांच सीटों पर कब्जा जमाने की है।

अखिलेश यादव का यह कदम यूपी में कांग्रेस के लिए एक मुश्किल स्थिति उत्पन्न कर सकता है। कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव में छह सीटें जीतने के बाद से उत्तर प्रदेश में अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने की योजना बनाई है। राहुल गांधी लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं और कांग्रेस ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का लक्ष्य रखा है। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस उपचुनाव में सपा की अपेक्षाओं को पूरा कर पाएगी।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी सपा ने 10 सीटों पर अपना दावा ठोका है। पार्टी ने मुंबई और ठाणे जैसे क्षेत्रों में मुस्लिम बहुल और उत्तर भारतीय मतदाताओं वाली सीटों पर ध्यान केंद्रित किया है। सपा ने महाराष्ट्र में अपने विधायकों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है और अब चुनावी मैदान में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रही है।

अखिलेश यादव ने हरियाणा में कांग्रेस को पूरा समर्थन देकर एक स्पष्ट संदेश दिया है कि सपा की प्राथमिकता बीजेपी को हराना है। अब कांग्रेस को यह तय करना होगा कि वह इस समर्थन का जवाब कैसे देती है। अगर कांग्रेस ने सपा की उम्मीदों को पूरा नहीं किया और यूपी और महाराष्ट्र में सपा की अपेक्षाओं को नजरअंदाज किया, तो इसका असर दोनों दलों के रिश्तों पर पड़ सकता है।

हरियाणा में सपा द्वारा दिखाए गए त्याग के बाद, कांग्रेस पर दबाव है कि वह यूपी और महाराष्ट्र में सपा को उचित सम्मान दे। कांग्रेस को यह साबित करना होगा कि वह सपा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर सकती है और बीजेपी के खिलाफ एक प्रभावी मोर्चा बना सकती है। अगर कांग्रेस ने इस मौके को सही तरीके से इस्तेमाल किया, तो यह चुनावी गठबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

सपा और कांग्रेस के बीच का यह राजनीतिक खेल न केवल हरियाणा, यूपी, और महाराष्ट्र की राजनीति को प्रभावित करेगा, बल्कि पूरे विपक्षी गठबंधन की राजनीति पर भी गहरा असर डालेगा। अखिलेश यादव ने हरियाणा में दिखाए गए त्याग के साथ एक नई राजनीतिक दिशा दी है, और अब कांग्रेस को यह साबित करना होगा कि वह इस समर्थन का सही इस्तेमाल कर सकती है। कांग्रेस और सपा के रिश्तों का भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि वे अपने राजनीतिक लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करते हैं और एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बना सकते हैं।

इस तरह, अखिलेश यादव का हरियाणा चुनाव से पीछे हटना और कांग्रेस को समर्थन देना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय है जो भारतीय राजनीति के मौजूदा परिदृश्य को बदल सकता है। यह निर्णय केवल सपा और कांग्रेस की राजनीति पर ही असर डालने वाला नहीं है, बल्कि यह बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन की एकजुटता को भी दर्शाता है।

'दुबई-कनाडा में करोगे नौकरी', लड़कियां बेरोजगारों को झांसे में लेकर करतीं ठगी; कॉल सेंटर का भंडाफोड़

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा पुलिस ने शनिवार को एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। यहां से छह युवतियों समेत नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया। कॉल सेंटर सेक्टर 63 में चल रहा था। आरोपी लोगों को विदेशों में नौकरी कराने का झांसा देते उसके बाद उनसे ठगी करते थे। वह वीजा दिलाने के नाम पर भी ठगी करते थे।

नोएडा। वर्क वीजा पर कनाडा व सर्बिया में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले कॉल सेंटर का सेक्टर-63 थाना पुलिस टीम ने शनिवार को पर्दाफाश किया। यहां डेढ़ साल से कॉल सेंटर संचालित हो रहा था। केरल, श्रीनगर, तमिलनाडु के पीड़ितों की शिकायत मिलने पर पुलिस को फर्जीवाड़े का पता चला। पुलिस ने आईटी एक्ट, धोखाधड़ी, जबरन वसूली व विश्वासघात की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। डायरेक्टर दंपती और छह महिलाओं समेत नौ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।

कंपनी खोलकर की जा रही थी धोखाधड़ी

डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्तिमोहन अवस्थी ने बताया कि एक माह पूर्व साइबर हेल्प डेस्क को ई ब्लॉक में बियोंड स्पार्क ओवरसीज नाम की कंपनी विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधडी करने की जानकारी मिली। केरल के त्रिवेंद्रम के प्रमोद राघवन समेत कई पीड़ितों की शिकायत पर जांच के दौरान कंपनी कार्यालय पर सोनू कुमार से पूछताछ की गई।

फेसबुक-इंस्टाग्राम से निकालते थे डिटेल

उसने खुद को प्रबंधक बताया और डायरेक्टर पंकज व मनप्रीत कौर के कहने पर फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि से विदेश जाने के इच्छुक लोगों की डिटेल निकालते हैं। कंपनी की सेल्स टीम से कॉल कराकर कनाडा में अपने रिश्तेदार के रॉयल इंडियन सुपरमार्केट एंड किचन नाम के मॉल में स्टोर कीपर, स्टोर सुपरवाइजर, एडमिन आदि पदों पर नौकरी दिलवाने का झांसा देते थे।

एक लाख से ज्यादा सैलरी देने का झांसा

प्रतिमाह 1.5 से दो लाख रूपये सैलरी की बात कहकर आवेदन कराते थे। स्टोर कीपर के नाम पर पांच लाख रुपये, स्टोर सुपरवाइजर के लिए 15 लाख रुपये और अन्य पदों के अनुसार पैसे लेते थे। कुल रकम का 10 प्रतिशत आवेदक से फाइल चार्ज के रूप में और शेष धनराशि धीरे-धीरे कर ली जाती थी।

दूर के लोगों से करते थे ठगी

शिकायत से बचने के लिए दूरदराज के राज्यों के आवेदकों को चुनते और ऑनलाइन पासपोर्ट, आधार कार्ड ले लेते। आवेदकों को विश्वास दिलाने के लिए कनाडा गये हुए लोगों के कागजातों में ग्राफिक चेंज कराकर भेजते देते। फर्जी तरीके से कनाडा में बैठे स्टाफ से इंटरव्यू और कॉल भी कराते।

हर लीड पर मिलता था कमीशन

उप निरीक्षक मनेंद्र प्रताप सिंह ने बताया किस्टाफ को सैलरी के अलावा 20 प्रतिशत तक कमीशन भी मिलता था। शेष धनराशि प्रबंधक व डायेक्टर में बंटती थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने अभी तक एक भी व्यक्ति की नौकरी नहीं लगवाई है। वह फर्जीवाड़ा पकड़े जाने और पैसे नहीं लौटाने के लिए कागजातों में कमी निकॉल टरकाते थे। इमिग्रेसन डिपार्टमेंट का अडंगा होने और जांच चलने का भी हवाला देते। वहां की रिपोर्ट लगाकर 45 दिन में लौटाने का हवाला देते थे।

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV
Drive the Future

चीन ईवी शुल्क पर कनाडा के साथ बातचीत करने को इच्छुक

परिवहन विशेष न्यूज

कनाडा द्वारा चीनी निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद चीन ने विश्व व्यापार संगठन में विवाद को सुलझाने के लिए द्विपक्षीय वार्ता का अनुरोध किया है। कनाडा ने पिछले महीने टैरिफ की घोषणा की थी। इसमें चीनी स्टील और एल्युमीनियम उत्पादों पर 25 प्रतिशत शुल्क शामिल है। यह उपाय अक्टूबर से प्रभावी होगा।

चीन के वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि वार्ता का अनुरोध विश्व व्यापार संगठन प्रक्रियाओं के अनुसार किया गया है। चीन ने कनाडा पर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करने का आरोप लगाया है और उससे विश्व व्यापार संगठन नियमों का पालन करने का आह्वान किया है।

इस महीने की शुरुआत में चीनी सरकार ने कहा कि वह कनाडा से सरसों के सफेद आयात की डंपिंग रोधी जांच शुरू करेगी। चीन कनाडा से रसायनों के आयात की भी जांच करने की योजना बना रहा है। कनाडा के टैरिफ के जवाब में ये कदम उठाए जाने की संभावना है।

ईवी की बढ़ती मांग के साथ बैटरी उद्योग में आएगा 90 अरब डॉलर का निवेश, इतने हजार रोजगार होंगे सृजित

परिवहन विशेष न्यूज

बैटरी निर्माण उद्योग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी और संबंधित घटक विनिर्माण क्षेत्र अगले 5 वर्षों में 90 बिलियन डॉलर (7.5 लाख करोड़ रुपये) का निवेश आकर्षित कर सकता है। इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस के अनुसार एसीसी विनिर्माण उद्योग में इस अवधि के दौरान 50,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने की भी क्षमता है। इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस भारत में एसीसी फैक्ट्रियों की स्थापना और कमीशन करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को व्यावसायिक वीज़ा जारी करने के लिए एसीसी-पीएलआई बोली विजेताओं और गैर-पीएलआई कंपनियों के बीच नीति समानता की मांग कर रहा है। सरकार ने घोषणा की है कि पीएलआई योजना या पीएलआई के तहत भारतीय कंपनियों द्वारा नियुक्त किए जा रहे विदेशी विषय वस्तु विशेषज्ञों/इंजीनियरों/तकनीशियनों को 6 महीने की अवधि के लिए बहु-प्रवेश व्यावसायिक वीज़ा दिया जाएगा।

यह स्थापना और कमीशनिंग, गुणवत्ता जांच के साथ आवश्यक रखरखाव, उत्पादन, आईटी और डीआरपी रैंप-अप, प्रशिक्षण, सूचीबद्ध विक्रेताओं के लिए आपूर्ति श्रृंखला विकास, संयंत्र डिजाइन आदि पर लागू होगा। इस कदम का स्वागत करते हुए, इंडिया एनर्जी स्टोरेज एलायंस (आईईएसए) के अध्यक्ष देबी प्रसाद दास ने कहा कि इससे अगले पांच वर्षों में भारत में एसीसी बैटरी और बैटरी घटक कारखानों के अतिरिक्त 100+ गीगावॉट विकसित करने के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा, ₹इसके अतिरिक्त, यह एसीसी आयात के कारण विदेशी मुद्रा की कमी को दूर करेगा और चीन और अन्य देशों पर भारत की निर्भरता को कम करेगा।"

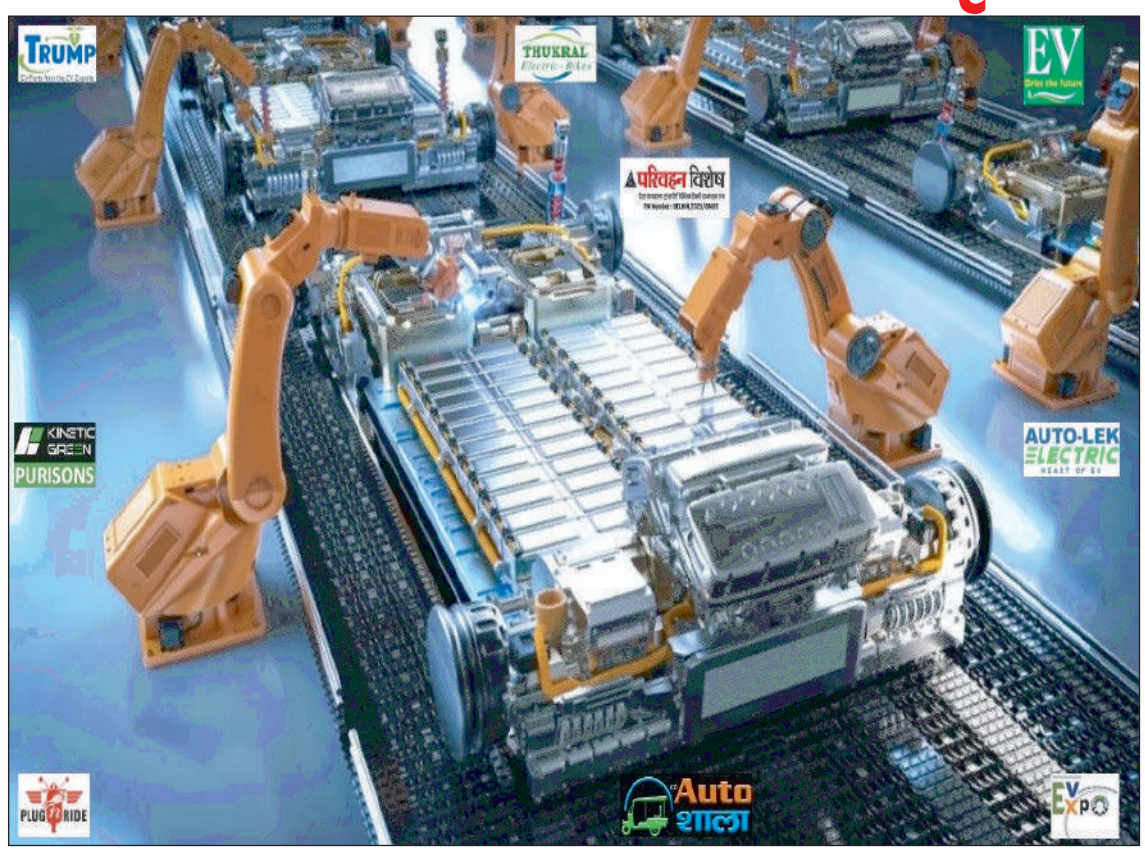

वैश्विक ईवी विनिर्माण केंद्र बनने के लिए भारत को ईवी और उनके घटकों के लिए एक व्यापक और स्वदेशी मूल्य श्रृंखला विकसित करनी होगी। वर्तमान में एसीसी बैटरियों का विनिर्माण (जो ईवी की लागत का कम से कम 50 प्रतिशत है) भारत में शुरुआती चरण की अवस्था में है। भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत में 50 गीगावाट स्वदेशी एसीसी विनिर्माण स्थापित करने के लक्ष्य के साथ 2022 में पीएलआई एसीसी योजना शुरू की।

मर्सिडीज ने ई-कारों के प्रति केंद्र सरकार के रुख को सराहा

परिवहन विशेष न्यूज

मर्सिडीज-बेंज इंडिया तेल-गैस इंजन वाली कारों से इलेक्ट्रिक कारों की दिशा में बढ़ने के प्रति केंद्र सरकार के 'स्पष्ट रुख और ध्यान' की सराहना करती है। मर्सिडीज-बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्य अधिकारी संतोष अय्यर ने आज बिजनेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी दी। वह दो दिन पहले भारत के जी20 शेरपा अमिताभ कांत के बयान के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि देश 'लंबे समय तक' इलेक्ट्रिक कारों पर पांच प्रतिशत और हाइब्रिड कारों पर 48 प्रतिशत कर जारी रखेगा।

अय्यर ने कहा, 'मुझे लगता है कि यह बहुत ही स्वागत योग्य बयान है। हम इलेक्ट्रिक कारों पर सरकार के रुख और इलेक्ट्रिक कारों की दिशा में बढ़ने के मामले में काफी स्पष्ट प्रयास की सराहना करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक कार की तकनीक महंगी है। आपको शुरुआत में इन्हें अपनाने वालों के लिए समर्थन की जरूरत होती है। कई साल की अवधि के दौरान जब तकनीक की लागत कम होगी, तो इसके साथ (अन्य कारों के साथ-साथ) समान बर्ताव किया जा सकता है।'

मर्सिडीज-बेंज ने गुरुवार, 05 सितंबर को अपने काफी महंगी कार मेबैक ईक्यूएस 680 स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) को 2.25 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर पेश किया। यह भारत में पेश की जाने वाली पहली इलेक्ट्रिक मेबैक कार है। मेबैक इस जर्मन कंपनी का टॉप एंड लग्जरी कार मॉडल है।

उन्होंने कहा 'मुझे लगता है कि सरकार सभी सही काम कर रही है। केंद्र सरकार के स्तर पर उनके पास इलेक्ट्रिक कारों, जिन पर पांच प्रतिशत जीएसटी है और अन्य प्रकार की कारों के बीच स्पष्ट अंतर है। राज्य सरकारों के स्तर पर उनमें से ज्यादातर इलेक्ट्रिक कारों पर शून्य सड़क कर की पेशकश कर रही हैं। इससे ईवी की कीमतें कम हो जाती हैं। इससे निश्चित रूप से ईवी अपनाने में मदद मिलती है।'

चूंकि भारत का लक्ष्य साल 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनना है, इसलिए देश में वाहन विनिर्माता भविष्य की सर्वोत्तम राह को लेकर बंटे हुए हैं। मारुति सुजूकी, टोयोटा और होंडा जैसी जापान की दिग्गज कंपनियां हाइब्रिड कारों पर कर कटौती के लिए जोर दे रही हैं। उनका तर्क है कि अकेले ईवी ही उत्सर्जन कम करने का पूरा बोझ नहीं उठा सकते हैं। अलबत्ता टाटा मोटर्स, ह्युंडै, किया और महिंद्रा ऐंड महिंद्रा जैसी कार विनिर्माता कंपनियां इस बात पर जोर दे रही हैं कि ईवी के प्रति पूरी पक्के वादे से ही भारत की सड़कों को सही मायने में कार्बन मुक्त किया जा सकता है।

हर कोई कर रहा है इस इलेक्ट्रिक कार के लॉन्च का इंतजार...

परिवहन विशेष न्यूज

चीन इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में तेजी से अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। कंपनी ने ऐसी बैटरी तकनीक विकसित की है जो जल्दी चार्ज होती है और ज्यादा रेंज देती है। पिछले साल चीन के बेस्ट्यून ब्रांड श्याओमी ने एक छोटी इलेक्ट्रिक लॉन्च की थी। इस कार के साथ कंपनी माइक्रो-ईवी सेगमेंट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है। FAW बेस्ट्यून श्याओमी का सीधा मुकाबला वुलिंग होंगुआंग मिनी ईवी से होगा। चीन में माइक्रो इलेक्ट्रिक कारों की सबसे ज्यादा डिमांड है। बेस्ट्यून श्याओमी की कीमत 30,000 से 50,000 युआन (करीब 3.47 लाख रुपये से 5.78 लाख रुपये) के बीच है। उम्मीद है कि इसे जल्द ही भारतीय बाजार में लाया जाएगा। इसका सीधा मुकाबला टाटा टियागो ईवी और एमजी कॉमेट ईवी से होगा।

FAW ने 2023 की शुरुआत में अप्रैल में शंघाई ऑटो शो में बेस्ट्यून श्याओमी को पेश किया था। इसके हार्डटॉप और कन्वर्टिबल दोनों वेरिएंट पेश किए गए थे। फिलहाल हार्डटॉप वेरिएंट बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह तय नहीं है कि भविष्य में कन्वर्टिबल वेरिएंट को बिक्री के लिए लाया जाएगा या नहीं। इस कार में टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट भी है, जो 7 इंच की यूनिट है। डैशबोर्ड में आकर्षक डुअल-टोन थीम है। श्याओमी में डुअल-टोन कलर स्कीम है, जो सीधे किसी एनिमेशन फिल्म की तरह लगती है। इसमें अधिक आकर्षक प्रोफाइल के लिए गोल किनारों के साथ बड़े चौकोर हेडलैंप हैं। श्याओमी ने एयरोडायनामिक व्हील्स का इस्तेमाल किया है जो रेंज बढ़ाने में उपयोगी हो सकते हैं।

बेस्ट्यून श्याओमी FME प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित है। इसमें ईवी और रेंज एक्सटेंडर डेडिकेटेड चेसिस शामिल हैं। इससे पहले NAT नामक एक राइड-हेलिंग ईवी को इस प्लैटफ़ॉर्म पर बनाया गया था। FME प्लेटफ़ॉर्म में दो A1 और A2 सब-प्लेटफ़ॉर्म हैं। A1 सब-प्लेटफ़ॉर्म 2700-2850 mm के व्हीलबेस वाले सबकॉम्पैक्ट और कॉम्पैक्ट को पूरा करता है। A2 का इस्तेमाल 2700-3000 mm के व्हीलबेस वाली कारों के लिए किया जाता है। ईवी के लिए रेंज 800Km से ज़्यादा और एक्सटेंडर के लिए 1200Km से ज़्यादा है। दोनों प्लैटफ़ॉर्म 800 V आर्किटेक्चर को सपोर्ट करते हैं।

माइक्रो-ईवी को पावर देने के लिए 20 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर लगी है। इसे रियर शाफ्ट पर रखा गया है। इस्तेमाल की गई बैटरी लिथियम-आयरन फॉस्फेट यूनिट है, जिसे गोशन और REPT द्वारा सप्लाई किया जाता है। पावरट्रेन के बारे में अधिक जानकारी अभी सामने आनी बाकी है। सुरक्षा के लिहाज से बेस्ट्यून श्याओमी में ड्राइवर साइड एयरबैग है। इसमें 3-दरवाजे हैं। बेस्ट्यून श्याओमी 3000 मिमी लंबी, 1510 मिमी चौड़ी और 1630 मिमी ऊंची है। इसका व्हीलबेस 1,953 मिमी है।

काइनेटिक ग्रीन ने बी2सी में की एंट्री

परिवहन विशेष न्यूज

ई-लूना बनाने वाली कपंनी काइनेटिक ग्रीन ने बी2सी यानी बिजनेस-टू-कंज्यूमर इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर सेगमेंट में एंट्री का एलान किया है। कंपनी एक बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर आधारित इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों की नई रेंज पेश की।

बेहतर प्रदर्शन के लिए इन व्यावसायिक तीन पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। जिससे ये ईवी फास्ट चार्जिंग के साथ आईसीई वाहनों की तरह ही बिना चिंता के लंबी दूरी की यात्राएं कर सकेंगी। कंपनी के उत्पाद को वित्त वर्ष 2025 की आखिरी तिमाही में पेश किए जाने की उम्मीद है।

काइनेटिक ग्रीन की संस्थापक और सीईओ सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी ने मीडिया को जानकारी दी कि ई लूना और ई-रिक्शा के जरिए सफलता हासिल करने के बाद, हमारा मकसद आम जनता के लिए ग्रीन मोबिलिटी प्रदाता बनना है और हम दोपहिया और तीन पहिया वाहनों के क्षेत्र में बदलाव लाएंगे। साथ ही लगातार बढ़ रहे भारतीय इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर मार्केट की लगभग 100 प्रतिशत मांग को पूरा किया जा सके।

नई थ्री-व्हीलर की रेंज के साथ ही काइनेटिक ग्रीन ने अपने एक्स्ट्रा फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशन से भी पर्दा उठाया। यह वाहन की बैटरी को 15 मिनट में कम समय में फुल चार्ज कर देता है। जिससे वाहन 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकता है। कंपनी के पास इस समय 100 चार्जिंग स्टेशन हैं। कंपनी का लक्ष्य इस वित्त वर्ष में तक इनकी संख्या को 250 करना है, जिसके बाद कंपनी इन ईवी चार्जर्स का दायरा 1000 स्थानों तक बढ़ाना चाहती है।

इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता एक फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर पर भी काम कर रहा है। जिसके अगले 18 महीनों में बाजार में आने की उम्मीद है। हालांकि, फिरोदिया ने कहा है कि काइनेटिक ग्रीन का भारतीय बाजार में तेजी से फैल रहे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में एंट्री करने का कोई इरादा नहीं है।

वह अपनी आइकॉनिक लूना के इलेक्ट्रिक अवतार ई-लूना को कंपनी के लिए काफी अहम मानती हैं। मोटवानी ने कहा कि यह इलेक्ट्रिक स्कूटर एक अर्बन लुक वाला होगा। उन्होंने यह भी कहा कि आनेवाला यह फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी के ई-लूना के साथ पोजिशन किया जाएगा।

फिरोदिया मानती हैं कि भारत में इलेक्ट्रिक कार नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक दोपहिया और तीन पहिया वाहनों से ईवी क्रांति होगी।

फिरोदिया के मुताबिक भारतीय ईवी परिदृश्य में दोपहिया और तीन पहिया इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट सबसे अहम हैं। यह अंतिम-मील की कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा, ₹हम ई मोबिलिटी को सुलभ और किफायती बनाना चाहते हैं। यह हमारे लिए एक बड़ा मौका है। और हमारी योजना 2030 तक अपने राजस्व को 10,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की है।₹ इस राजस्व का 60 प्रतिशत हिस्सा कंपनी के दोपहिया कारोबार से आने का अनुमान है।

उन्होंने कहा, "उस समय तक हम 10 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बना लेंगे, जिसमें एक लाख तीन पहिया वाहन और 10 लाख दो पहिया वाहन शामिल होंगे। जो राजस्व में क्रमशः 3,500 करोड़ रुपये और 6,000 करोड़ रुपये का योगदान देंगे। शेष 500 रुपये करोड़ गोल्फ कार्ट जेवी से आएंगे।" इस साल अगस्त की शुरुआत में, कंपनी ने सीरीज ए राउंड में ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल से 25 मिलियन डॉलर जुटाए और 15 मिलियन डॉलर और जुटाने वाली है। कंपनी उत्पादन बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के सुपा में एक नया मैन्युफेक्चरिंग प्लांट स्थापित किया था। यह रिसर्च एंड डेवलपमेंट और बाजार विस्तार में निवेश करने के लिए 15 मिलियन डॉलर और जुटाने की योजना बना रही है।

फिरोदिया मोटवानी ने कहा, ₹हम 3.0 के साथ अपने अगले चरण का एलान कर रहे हैं। यह आक्रामक पैमाने पर विस्तार और अपनी मौजूदगी बढ़ाने का समय है। इसके साथ ही और भी बहुत कुछ होने वाला है।"

काइनेटिक ग्रीन अगले 4-5 वर्षों में अपनी बाजार हिस्सेदारी 10 प्रतिशत तक होने की उम्मीद कर रही है। क्योंकि कंपनी आने वाले वर्षों में दक्षिण एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बाजारों में निर्यात करेगी।

कंपनी का दावा है कि इन नए उत्पादों के साथ, अब L3 और L5 के साथ इस सेगमेंट में इसका सबसे बड़ा उत्पाद पोर्टफोलियो है। इससे बाजार 10 प्रतिशत से बढ़कर 100 प्रतिशत हो जाएगा। ये उत्पाद 1.2 लाख रुपये से 4.5 लाख रुपये तक की रेंज में उपलब्ध होंगे।

फिरोदिया मोटवानी को उम्मीद है कि इस दशक के आखिर तक देश में इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों की पहुंच 75 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। उनका कहना है कि दशक के आखिर तक इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों का बाजार 40,000 करोड़ रुपये तक बढ़ जाएगा।

काइनेटिक ग्रीन ने भारत में अब तक 1200 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व के साथ 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बेचे हैं।

इस दशक के आखिर तक कंपनी को 3,400 करोड़ रुपये के कारोबार के साथ लगभग 1.5 लाख तीन पहिया वाहन बेचने की उम्मीद है।

गाजियाबाद के अंबेडकर रोड पर लगा ई-रिक्शा का प्रतिबंध

परिवहन विशेष न्यूज

ग़रीबों के रोज़गार का ज़रिया बन चुके ई-रिक्शा गाजियाबाद के अंबेडकर रोड पर यातायात को बाधित कर रहे हैं। यही वजह है कि गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस को मुख्य सड़कों पर ई-रिक्शा पर प्रतिबंध लगाना पड़ रहा है। एनएच-9 और फिर हापुड़ रोड के बाद अब ट्रैफिक पुलिस ने अंबेडकर रोड पर ई-रिक्शा पर प्रतिबंध लगाने का फ़ैसला लिया है।

अपर पुलिस उपायुक्त पीयूष कुमार सिंह ने बताया कि डीसीपी सिटी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुपालन में 12 सितंबर से अंबेडकर रोड पर ई-रिक्शा का परिचालन सुबह सात बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रतिबंधित होगा।

अपर पुलिस उपायुक्त पीयूष कुमार सिंह ने बताया कि अंबेडकर रोड पर पुराना बस अड्डा से मालीवाड़ा और कालकागढ़ चौक होते हुए चौधरी मोड़ तक ई-रिक्शा के परिचालन को पूर्णः प्रतिबंधित किया गया है। 12 सितंबर से सुबह सात बजे से लेकर रात दस बजे तक तक इस रोड पर आने वाले ई-रिक्शा के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

2 सितंबर से यातायात पुलिस ने हापुड़ रोड पर ई-रिक्शा का परिचालन प्रतिबंधित कर दिया था। हापुड़ रोड पर पुराना बस अड्डा से डासना आरओबी के बीच ई-रिक्शा का परिचालन रोका गया है, हालांकि नया बस अड्डा और पुराना बस अड्डा के बीच परिचालन को भी अभी नहीं रोका गया है। एनएच-9 पर उससे पहले ही ई-रिक्शा प्रतिबंधित किए जा चुके हैं।

यातायात पुलिस का कहना है कि कम गति होने के कारण ई-रिक्शा जाम का कारण बन जाता है। इसके अलावा मुख्य मार्गों पर दुर्घटना होने का भी खतरा रहता है।

महिलाओं के सम्मान के बिना समाज खोखला है

विजय गर्ग

हमारे देश में 16 करोड़ गृहिणियां हैं जो घरेलू काम के बदले में कुछ नहीं मांगतीं। नैतिकता और मानवता के नाम पर एक महिला को घर का काम करना पड़ता है लेकिन इस पर प्रतिबंध है। महिला की सेवा के बदले मनपसंद पोशाक भी बदल दी जाती है। महिला अपनी सेवाओं के बदले में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करती है, लेकिन पुरुष प्रभुत्व का असर उल्टा पड़ता है।

यदि किसी महिला को उसकी सेवाओं के बदले में धन नहीं दिया जा सकता है, तो परिवार में उसकी स्थिति सम्मानजनक और गौरवपूर्ण होनी चाहिए। महिला की सेवाओं को महत्व देना और उसके मूल्य को अपने बराबर समझना हमारा नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। अभी भी महिलाओं के सामने सभी पहलुओं में चुनौतियां हैं लेकिन महिलाओं को महिलाओं का समर्थन करना चाहिए। महिलाओं के सम्मान के बिना समाज खोखला है एक महिला सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक नैतिक स्वभाव रखते हुए समर्पित भाव से घर चलाती है ।जननी है गुरबाणी ने ब्रह्माण्ड की भावपूर्ण नारी की कीमत लिखी है। पहले महिलाओं को नौकरानी समझा जाता था. चूंकि समाज की नींव महिला है, इसलिए समाज और घर में उसकी सेवाएं अतुलनीय हैं। एक महिला जिस भी पेशे से जुड़ी हो, उसमें अपना योगदान देती है। उनकी सेवाओं के बिना समृद्धि संभव नहीं है. गृहिणियों को दिन-रात दो से अधिक शिफ्टों में काम करना पड़ता है, जबकि कामकाजी महिलाओं को घर आने के बाद भी बार-बार काम करना पड़ता है। अधिकांश देशों में महिलाओं को उनके घरेलू काम के लिए महत्व नहीं दिया जाता है। यह वह हैइसे कर्तव्य माना जाता है, अधिकारों से वंचित किया जाता है। हमारे देश में 16 करोड़ गृहिणियां हैं जो घरेलू काम के बदले में कुछ नहीं मांगतीं। नैतिकता और मानवता के नाम पर एक महिला को घर का काम करना पड़ता है लेकिन इस पर प्रतिबंध है। महिला की सेवा के बदले मनपसंद पोशाक भी बदल दी जाती है। महिला अपनी सेवाओं के बदले में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करती है, लेकिन पुरुष प्रभुत्व का असर उल्टा पड़ता है। मनरेगा ने कुछ हद तक महिलाओं को सेवा का मूल्य दिया है। उनका मुआवजा सीधे खाते में जाता है. उसके आलावाएक ठोस कानूनी और नैतिक प्रक्रिया महिलाओं की सेवा को महत्व देने से दूर हो जाती है। सुबह उठने से लेकर देर रात सोने तक उनकी सेवा लगातार जारी रहती है. सारे काम की जिम्मेदारी लेने के बाद भी वह एहसान नहीं जताती। एक गृहिणी के रूप में एक महिला का काम उस फूल की तरह है जिसकी खुशबू उसकी कीमत से अधिक मूल्यवान है। उसी प्रकार एक घरेलू कामगार को एक नेक महिला का दर्जा मिलता है। स्त्री गृहिणी और आत्मवान भी होती है। महिलाओं के सम्मान के बिना समाज खोखला है। मद्रास हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनायाकि 'पत्नी काम करके घर का माहौल आरामदायक बनाती है।' इसलिए परिवार में उनका योगदान निश्चित रूप से कोई मामूली काम नहीं है। यह बिना किसी छुट्टी के 24 घंटे काम करता है। इसकी तुलना पति की 8 घंटे की ड्यूटी से नहीं की जा सकती।' 2011 की जनगणना के मुताबिक, 15.98 करोड़ महिलाएं अपना मुख्य व्यवसाय घर का काम करती हैं। रिश्तों और बच्चों के भविष्य को बनाए रखने के लिए महिलाओं को अपनी सेवा सीमित करने के लिए मजबूर किया जाता है हैं अंततः परिस्थिति से समझौता करना ही पड़ता है. समाज और अपने घर की सेवा के मूल्य के बिनाख़ुश करना एक महिला का हिस्सा है। यदि किसी महिला को उसकी सेवाओं के बदले में धन नहीं दिया जा सकता है, तो परिवार में उसकी स्थिति सम्मानजनक और गौरवपूर्ण होनी चाहिए। महिला की सेवाओं को महत्व देना और उसके मूल्य को अपने बराबर समझना हमारा नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। महिलाओं के सामने अभी भी सभी पहलुओं में चुनौतियाँ हैं लेकिन महिलाओं को रसोई और अन्य घरेलू कार्यों में आत्मनिर्भर होने के लिए और अधिक कदम उठाने चाहिए। एक घर एक महिला के शरीर और आत्मा का एक संयोजन है।

सेवानिवृत्त प्राचार्य शिक्षा स्तंभकार
मलोट पंजाब

संपादक की कलम से

भारत को विदेश नीति का पुन: मूल्यांकन करना होगा

शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से नई दिल्ली की सबसे स्थायी और सुसंगत विदेश नीति रणनीतियों में से एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी (AEP) रही है। शुरू में लुक ईस्ट पॉलिसी के रूप में शुरू की गई यह विदेश नीति मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक और...

शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से नई दिल्ली की सबसे स्थायी और सुसंगत विदेश नीति रणनीतियों में से एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी (AEP) रही है। शुरू में लुक ईस्ट पॉलिसी के रूप में शुरू की गई यह विदेश नीति मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित थी। समय के साथ, यह दृष्टिकोण एक व्यापक रणनीति में विकसित हुआ है, जिसमें जापान और दक्षिण कोरिया जैसे पूर्वी एशियाई देशों के साथ गहन जुड़ाव और सीमा पार आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देकर भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की आर्थिक और रणनीतिक जरूरतों को देखना शामिल है। हालांकि, पड़ोसी बंगलादेश और म्यांमार में हाल की राजनीतिक अस्थिरता ने नीति की प्रभावशीलता के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा की हैं, जो दर्शाता है कि अब एक महत्वपूर्ण पुनर्मूल्यांकन आवश्यक हो सकता है।

पड़ोस में अचानक बदलाव : अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार को हटाने के साथ बंगलादेश में राजनीतिक परिदृश्य में एक नाटकीय बदलाव आया। हसीना का प्रशासन, जिसे लंबे समय से भारत के लिए एक स्थिर और मैत्रीपूर्ण पड़ोसी के रूप में देखा जाता था, व्यापक विरोध के बीच गिर गया। भारत के लिए, जिसने हसीना की सरकार के साथ एक मजबूत संबंध विकसित किया था, यह विकास के लिए एक महत्वपूर्ण झटका है। इस बदलाव ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है और भारत के रणनीतिक हितों के लिए कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और कनैक्टिविटी परियोजनाओं पर संदेह पैदा कर दिया है।

इस राजनीतिक उथल-पुथल के तत्काल नतीजों में ट्रेन सेवाओं का निलंबन और भारत-बांग्लादेश सीमा पर माल और लोगों की आवाजाही को रोकना शामिल है। विडंबना यह है कि भारत के लिए एक और अधिक चिंताजनक बात यह है कि बंगलादेश में नया नेतृत्व अपना झुकाव चीन या पाकिस्तान की ओर मोड़ सकता है, जिनके उत्पात के कारण ही सबसे पहले बंगलादेश का निर्माण हुआ, ऐसे देश जिनके साथ भारत के जटिल और अक्सर प्रतिकूल संबंध हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अध्यक्षता वाली बंगलादेश की अंतरिम सरकार, बंगलादेश और भारत के बीच पहले से मौजूद घनिष्ठ सहयोग को बनाए रखने के लिए कम इच्छुक हो सकती है। इस तरह के बदलाव के परिणामस्वरूप भू-राजनीतिक पुनर्संरेखण हो सकता है जो भारत के सुरक्षा और आर्थिक हितों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।

अंतरिम सरकार के साथ संबंधों को संभालना भारत के लिए मुश्किल हो सकता है। यूनुस प्रशासन ने द्विपक्षीय संबंधों के संभावित पुनःमूल्यांकन का संकेत दिया है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि भारत के साथ पहले हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (एम.ओ.यू.) की समीक्षा की जा सकती है या उन्हें बंगलादेश के प्रतिकूल पाए जाने पर रद्द भी किया जा सकता है। यह, भारतीय-वित्तपोषित परियोजनाओं की बढ़ती जांच और तीस्ता जल-सांझाकरण संधि जैसे विवादास्पद मुद्दों पर नए सिरे से चर्चा के साथ, इस क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों को संरक्षित करने में भारत के सामने आने वाली जटिलताओं को उजागर करता है।

म्यांमार में जुड़ाव की दुविधा : भारत के लिए म्यांमार का रणनीतिक और आर्थिक महत्व काफी है, खासकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी (ए.ई.पी.) के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के प्रभाव को बढ़ाने और आसियान देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए। हालांकि, फरवरी 2021 में सेना के कब्जे से उपजी म्यांमार में राजनीतिक उथल-पुथल एक गंभीर चुनौती पेश करती है। 8 फरवरी, 2024 को, भारत सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और पूर्वोत्तर राज्यों में जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए सीमा पर बाड़ लगाने के बाद म्यांमार के साथ मुक्त आवागमन व्यवस्था (एफ.एम.आर.) को समाप्त करने का फैसला किया।

राय

100 दिन सरकार के मगर कोई फर्क नहीं

मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा भाषण अंग्रेजी में पढ़ पाया, इसके लिए इकोनॉमिक टाइम्स का शुक्रिया। उन्होंने हिंदी में बात की और मुझे लगता है कि अनुवाद सटीक था। मोदी ने अपनी सरकार को बधाई दी और वल्ड लीडर्स फोरम को बताया...

मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा भाषण अंग्रेजी में पढ़ पाया, इसके लिए इकोनॉमिक टाइम्स का शुक्रिया। उन्होंने हिंदी में बात की और मुझे लगता है कि अनुवाद सटीक था। मोदी ने अपनी सरकार को बधाई दी और वल्ड लीडर्स फोरम को बताया कि पिछले 10 वर्षों में 'हमारी अर्थव्यवस्था लगभग 90 प्रतिशत तक बढ़ गई है'। यह सराहनीय है अगर यह सही था। मेरे पास जो संख्याएं हैं, वे हैं-

वर्ष	स्थिर कीमतों पर जी.डी.पी.
31 मार्च 2014 को	98,01,370 करोड़ रुपए
31 मार्च 2024 को	173,81,722 करोड़ रुपए

वृद्धि 74,88,911 करोड़ रुपए थी और विकास कारक 1.7734 या 77.34 प्रतिशत की वृद्धि दर है। एक विकासशील देश के लिए यह भी अच्छा है। बेशक, किसी को उदारीकरण के बाद से पिछले 2 दशकों की दरों के साथ उस दर की तुलना करनी चाहिए। 1991-92 और 2003-04 (13 वर्ष) के बीच जी.डी.पी. (अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधि) का आकार दोगुना हो गया। फिर, 2004-05 और 2013-14 (यू.पी.ए. के 10 वर्ष) के बीच जी.डी.पी. का आकार दोगुना हो गया। मैंने अनुमान लगाया था कि मोदी के 10 वर्षों में जी.डी.पी. दोगुनी नहीं होगी और संसद में भी यही कहा था। प्रधानमंत्री ने अब इसकी पुष्टि की है। भारत की अर्थव्यवस्था वास्तव में बढ़ी है, लेकिन हम और बेहतर कर सकते थे।

बेरोजगारी-हाथी : अपने भाषण में, प्रधानमंत्री ने कहा, ''...आज, भारत के लोग नए आत्मविश्वास से भरे हुए हैं।'' कुछ दिन पहले ही हमने खबरें देखीं कि 395,000 उम्मीदवारों ने हरियाणा सरकार में 15,000 रुपए प्रति माह के वेतन पर अनुबंध के आधार पर सफाई कर्मचारी के पद के लिए आवेदन किया था, जिसमें 6,112 स्नातकोत्तर, 39,990 स्नातक और 117,144 ऐसे उम्मीदवार शामिल थे जिन्होंने कक्षा 12 तक पढ़ाई की थी। निश्चित रूप से, यह 'नए आत्मविश्वास' का संकेत नहीं है। मुझे पता है कि ऐसे समर्थक भी हैं जो इस कहानी की व्याख्या इस तरह से करेंगे कि पहले से ही नौकरी कर रहे लोग सरकारी नौकरी की सुरक्षा चाहते हैं! मैं उनकी कल्पना को तोडना नहीं चाहता। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 'भारत के महत्वाकांक्षी युवाओं और महिलाओं ने निरंतरता, राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए मतदान किया है।' कई पर्यवेक्षकों का मानना है कि वोट इसके विपरीत था। वोट बदलाव, संवैधानिक शासन और समानता के साथ विकास के लिए था। लक्ष्यों के 2 सैट एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। निरंतरता बनाम बदलाव, राजनीतिक स्थिरता बनाम संवैधानिक शासन और आर्थिक विकास बनाम समानता के साथ विकास। जिस तरह प्रधानमंत्री ने अपने लक्ष्यों के सैट को मंजूरी देने का मामला बनाने की कोशिश की, उसी तरह भाजपा के शासन के प्रति लोगों की अस्वीकृति और लक्ष्यों को फिर से निर्धारित करने की इच्छा के लिए एक शक्तिशाली तर्क दिया जा सकता है।

पुनः निर्धारित करना चाहता था : मैं इस कॉलम में 'बेरोजगारी' पर ही रहना चाहता हुं। सी.एम.आई.ई. के अनुसार, अखिल भारतीय बेरोजगारी दर 9.2 प्रतिशत है। कांग्रेस के घोषणापत्र 2024 में कहा गया है कि उदारीकरण के 33 साल बाद, 'आर्थिक नीति को फिर से निर्धारित करने का समय आ गया है'। घोषणापत्र में 'नौकरियों' पर 2 विशिष्ट प्रस्ताव रखे गए।

जी.एस.टी. काऊंसिल की बैठक पर टिकी निगाहें

वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) की दरों पर चर्चा के लिए जी.एस.टी. काऊंसिल की बैठक 9 सितम्बर को होने जा रही है। इस बैठक से पूर्व कर व्यवस्था में संभावित बदलावों पर काम कर रहे राज्यों के मंत्रियों के एक समूह ने संकेत दिया है कि फिलहाल उनकी योजना चार...

वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) की दरों पर चर्चा के लिए जी.एस.टी. काऊंसिल की बैठक 9 सितम्बर को होने जा रही है। इस बैठक से पूर्व कर व्यवस्था में संभावित बदलावों पर काम कर रहे राज्यों के मंत्रियों के एक समूह ने संकेत दिया है कि फिलहाल उनकी योजना चार दरों वाले मौजूदा ढांचे को बरकरार रखने की है। हालांकि अभी चर्चाएं चल रही हैं और कोई निर्णय नहीं लिया गया है लेकिन समूह के कुछ सदस्यों का कहना है कि चूंकि जी.एस.टी. व्यवस्था स्थिर हो चुकी है इसलिए शायद इसके साथ छेड़छाड़ करना उचित नहीं होगा। जी.एस.टी. परिषद की अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई में अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकार जी.एस.टी. कर ढांचे को सरल और युक्तिसंगत बनाने के प्रयास करेगी और इसे बाकी बचे क्षेत्रों तक विस्तार दिया जाएगा।

राज्यों के मंत्रिसमूह को इस प्रक्रिया की पहल करनी चाहिए। इस संबंध में सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि आगामी 9 सितंबर को होने वाली जी.एस.टी. परिषद की बैठक में इस विषय पर चर्चा की जाएगी। इस बीच देश भर के उद्योग और व्यापार जगत की नजरें भी काऊंसिल की इस महत्वपूर्ण बैठक पर लगी हुई हैं और उद्योग एवं व्यापार जगत भी इस बैठक से कर ढांचे में ऐसे बदलाव की उम्मीद कर रहा है जिस से अनुपालन में आसानी हो और व्यापारियों और ग्राहकों को भी राहत मिले।

तीन दरों वाले कर ढांचे पर हो सकता है विचार: परिषद इस बैठक में 3 दरों वाले ढांचे को अपनाने पर विचार कर सकती है। अनिवार्य वस्तुओं के लिए कर दर कम रखी जाए, अधिकांश वस्तुओं सेवाओं के लिए मध्यम दर रखी जाए और चुनिंदा वस्तुओं या नुकसानदायक वस्तुओं के लिए दरों को ऊंचा रखा जाए। यह सुझाव भी दिया गया है कि 12 और 18 प्रतिशत की स्लैब को मिलाकर 16 प्रतिशत का एक नया स्लैब तैयार किया जाए। इससे जटिलता में काफी कमी आएगी और दरों की बहुलता के कारण उत्पन्न विसंगतियों में से कई दूर होंगी। इसके अलावा समायोजन और दरों को सहज बनाने का काम इस प्रकार करना होगा कि समग्र जी.एस.टी. कर संग्रह राजस्व निरपेक्ष दर के करीब पहुंच सके। ध्यान देने वाली बात है कि कर संग्रह का बड़ा हिस्सा 18 फीसदी के स्लैब से आता है।

जी.एस.टी. काऊंसिल को उपकर पर भी लेना पड़ सकता है निर्णय : शुरूआती वर्षों में जी.एस.टी. दरों को समय से पहले कम कर दिया गया जिससे इसके प्रदर्शन में कमजोरी आई। हालांकि इस कर के क्रियान्वयन के बाद से संग्रह में प्रभावी इजाफा हुआ है। जैसा कि अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यन और अन्य लोगों ने लिखा है कि 2023-24 में उपकर समेत विशुद्ध जी.एस.टी. संग्रह सकल घरेलू उत्पाद (जी.एस.टी.) का 6.1 प्रतिशत था जो 2012-17 के जी.एस.टी. से पहले के दौर के लगभग समान था। यह भी ध्यान देने लायक है कि मौजूदा संग्रह में क्षतिपूर्ति उपकर भी शामिल है जिसे उस कर्ज को चुकाने के लिए जुटाया जा रहा है जो महामारी के दौरान राज्यों के राजस्व में कमी की भरपाई के लिए लिया गया था।

जी.एस.टी. परिषद को निकट भविष्य में कर्ज चुकता हो जाने के बाद कभी न कभी इस उपकर के बारे में निर्णय लेना होगा। एक सुझाव यह है कि इसे कर दर में शामिल किया जाए। हालांकि इससे उपभोक्ताओं के वास्तविक कर व्यय पर असर नहीं होगा लेकिन किसी भी निर्णय की सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि उपकर को सीमित समय के लिए लागू किया गया था और इसका एक खास उद्देश्य था- पहले 5 सालों में राज्यों के राजस्व में कमी की भरपाई के लिए संसाधन जुटाना। संग्रह जारी रहा क्योंकि सरकार को इस पूरी अवधि में राज्यों की भरपाई करनी पड़ी।

व्यापक तौर पर दरों को राजस्व निरपेक्ष दर के अनुसार समायोजित किया जाना चाहिए। इससे केंद्र और राज्य के स्तर पर राजस्व संग्रह में इजाफा होगा। बढ़ा हुआ राजस्व सरकार के दोनों स्तरों पर उच्च राजस्व को समायोजित करेगा। यह ऐसे समय में होगा जब देश को आम सरकारी बजट घाटा और सार्वजनिक ऋण कम करने की जरूरत है। इस विषय को टालने से जी.एस.टी. व्यवस्था के लिए जरूरी समायोजन में देरी होगी।

महिला स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए

आज के जटिल सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक परिवेश में, लोग न्याय की अपेक्षा करते हैं और न्याय होते हुए भी दिखते हैं। यह नि:संदेह एक आदर्श प्रस्ताव है। हालांकि, एक व्यक्ति का न्याय दूसरे व्यक्ति के लिए दु:स्वप्न बन सकता है क्योंकि इसमें कई तरह के नियम और...

आज के जटिल सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक परिवेश में, लोग न्याय की अपेक्षा करते हैं और न्याय होते हुए भी दिखते हैं। यह निःसंदेह एक आदर्श प्रस्ताव है। हालांकि, एक व्यक्ति का न्याय दूसरे व्यक्ति के लिए दुःस्वप्न बन सकता है क्योंकि इसमें कई तरह के नियम और कानून उलझे हुए हैं। ऐसा मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि यह कोई सीधा-सादा घोटाला नहीं है। इसमें कई चक्र हैं और कई बार यह जानना मुश्किल हो जाता है कि घोटाले का कौन-सा चक्र किसके इशारे पर और किसके फायदे के लिए घूम रहा है।

हालांकि अलग-अलग उद्देश्यों और विभिन्न कारणों और डिजाइनों के लिए चक्र घूमता रहता है। इसमें कई खिलाड़ी हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने-अपने एजैंडे या हित को आगे बढ़ा रहा है, या तो जांच प्रक्रिया में मदद करने के लिए या वास्तविक मुद्दों को भ्रमित करने के लिए। भले ही हम मामले को खुले दिमाग से, बिना किसी दुर्भावना या पूर्वाग्रह के देखने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जांच पैटर्न में कई ऐसे पहलू हैं जो इस बात पर भरोसा नहीं दिलाते कि मुद्दों को कैसे संभाला गया है।

फिर भी, हमें निष्पक्षता के सिद्धांतों को पहचानने का एक तरीका खोजना होगा। इस संदर्भ में, प्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रणालियों को ऐसा होना चाहिए। कहीं न कहीं सही और गलत के बीच फर्क करने के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी। सच को छिपाना मूर्खता है। महिलाओं को यौन दुराचार की शिकायत उच्चतम अधिकारियों से करने के लिए आगे आना होगा। केंद्र सरकार ने राज्यों से महिलाओं की सुरक्षा के लिए अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए पर्याप्त और प्रभावी उपाय करने को भी कहा है। यह केंद्र और राज्य सरकारों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बलात्कार के मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई है और नए बलात्कार विरोधी उपायों को तेजी से लागू किया है। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में 3 प्रमुख प्रावधानों के साथ एक सख्त बलात्कार विरोधी कानून पारित किया है। सबसे पहले, कानून में मृत्युदंड सहिता दंड की गंभीरता को बढ़ाया गया है, अगर हमले के कारण पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वह 'बेहोशी की हालत' में चली जाती है। दूसरा, कानून में यह अनिवार्य किया गया है कि प्रारंभिक रिपोर्ट के 21 दिनों के भीतर जांच पूरी हो जाए। तीसरा, यह बलात्कार के मामलों में अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग को प्रतिबंधित करता है, मुख्य रूप से ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए जो सरकार को शर्मिंदगी का कारण बन सकती है।

उदाहरण के लिए, 2 साल पहले, दिल्ली के होली फैमिली अस्पताल में एक नर्स ने सर्जरी के दौरान ऑपरेशन थिएटर तकनीशियन द्वारा यौन उत्पीड़न किए जाने की सूचना दी थी। हालांकि आंतरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) के होने के बावजूद, कई महिलाएं अभी भी लिखित शिकायत दर्ज करने से हिचकिचाती हैं। अस्पताल ने उसकी मौखिक शिकायत पर कार्रवाई की, लेकिन औपचारिक लिखित रिपोर्ट के बिना, बर्खास्तगी पत्र में तकनीशियन की बर्खास्तगी का कारण नहीं बताया गया। होली फैमिली अस्पताल ने सुरक्षित कार्यस्थल बनाने के लिए कई उपाय लागू किए हैं, जैसे लिंग-विशिष्ट आराम और चेंजिंग रूम, व्यापक सी.सी.टी.वी. कवरेज, नियमित सुरक्षा जांच और उत्पीड़न की रिपोर्ट करने की स्पष्ट प्रक्रियाएं इत्यादि।

फैडरेशन ऑफ रैजीडैंट डाक्टर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव डा. मीत घोनिया ने कहा कि सरकारी और निजी अस्पतालों में आई.सी.सी. अक्सर औपचारिकता मात्र होती है। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ डाक्टर इन समितियों के बारे में जानते होंगे, लेकिन नर्सिंग और हाऊसकीपिंग की भूमिकाओं में महिलाओं को आमतौर पर उचित अभिविन्यास कार्यक्रमों की कमी के कारण नहीं पता होता है। वास्तविक अमल की कमी कई महिला कर्मचारियों को उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के बढ़ते जोखिम के लिए उजागर करती है।

अस्पताल व्यापक सुरक्षा उपायों को अपनाकर और खुलेपन और समर्थन की संस्कृति विकसित करके सभी महिला कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित कर सकते हैं। सार्वजनिक अस्पतालों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नीतियों को लागू करना और ऐसी संस्कृति बनाना शामिल है, जहां महिलाएं प्रतिशोध के डर के बिना घटनाओं की रिपोर्ट करने में सक्षम महसूस करें। स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं को प्रतीकात्मक इशारों से आगे बढ़कर लिंग-विशिष्ट सुविधाओं, प्रभावी निगरानी, नियमित स्टाफ प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों जैसे ठोस उपायों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस मोर्चे पर प्रगति धीमी रही है। अस्पतालों को सभी कर्मचारियों के लिए सुरक्षित बनाने और हिंसा को बढ़ावा देने वाले सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने के लिए त्वरित, निर्णायक उपायों की आवश्यकता है। केंद्र और राज्य सरकारों और अस्पताल प्रशासन दोनों को इसे एक तत्काल प्राथमिकता के रूप में लेना चाहिए, जिससे सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा एक मौलिक अधिकार बन जाए, न कि एक विशेषाधिकार।

-हरि जयसिंह

गहने बेचने पर क्यों घट जाती है सोने की कीमत जौहरी के गणित में मेकिंग चार्ज का होता है सारा खेल

परिवहन विशेष न्यूज

क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम सोने के गहने सुनार को बेचने जाते हैं तो हाथ में आई राशि इतनी कम क्यों होती है। दरअसल यह सारा खेल मेकिंग चार्ज का होता है। सोने की वास्तविक कीमत तो कम होती है लेकिन सुनार सोने के गहने बेचने पर मोटा मेकिंग चार्ज वसूल लेते हैं जिसकी वजह से फाइनल बिल काफी बढ़ जाता है।

नई दिल्ली। गहने खरीदने जाते हैं तो गोल्ड रेट के अलावा, फाइनल बिल में जौहरी कई तरह के चार्ज जोड़ लेता है। यही वजह है कि 10 ग्राम सोने की कीमत जितनी होती है फाइनल बिल उससे ज्यादा ही बन जाता है। ठीक इससे उलट स्थिति में जब सोने के गहने बेचने जाते हैं तो बदले में हाथ आई राशि बहुत कम लगती है। दरअसल, यह सारा खेल मेकिंग चार्ज का होता है। सोने की वास्तविक कीमत तो कम होती है लेकिन सुनार सोने के गहने बेचने पर मोटा मेकिंग चार्ज वसूल लेते हैं, जिसकी वजह से फाइनल बिल काफी बढ़ जाता है।

क्या होता है मेकिंग चार्ज

मेकिंग चार्ज को कुछ इस तरह समझ सकते हैं। जब भी सोने के गहने लेने जाते हैं तो सोने को आभूषण के रूप में तैयार करने के लिए इस पर कारीगरों की मेहनत लगती है। गहने की सजावट के लिए कई तरह के स्टोन लगाए जाते हैं, जो कि श्रम का हिस्सा होता है। ऐसे सोने के गहने जिन्हें फाइलन टच देने के लिए कारीगरों का बहुत ज्यादा समय लगता है, पर मेकिंग चार्ज भी ज्यादा होता है। यह सोने के गहने पर बारिक काम के आधार पर तय होता है।

सोने पर कितना होता है मेकिंग चार्ज

दरअसल, मेकिंग चार्ज को लेकर कोई तय फॉर्मूला नहीं है। न ही मेकिंग चार्ज फिक्स्ड होते हैं। यह सुनार पर डिपेंड करता है वह कि कितना मेकिंग चार्ज ले रहा है। आमतौर पर सुनार 5% से लेकर 20-25% के बीच ही मेकिंग चार्ज वसूलते हैं।

मेकिंग चार्ज दो तरीके से लगाए जाते हैं

मेकिंग चार्ज लगाने के दो तरीके होते हैं

पहला- प्रति ग्राम सोने पर तय कीमतx कुल सोने का भार

दूसरा- सोने की कुल कीमत पर एक तय प्रतिशत

सोने के गहनों का रेट कैसे होता है फाइनल

मान लीजिए आपको 9 ग्राम सोने की चेन खरीदनी है। 22 कैरेट सोने का भाव खरीदारी के दिन 66,700/10 ग्राम बना हुआ है। सुनार आपसे 11 प्रतिशत मेकिंग चार्ज ले रहा है। गोल्ड चेन पर 3 प्रतिशत जीएसटी भी जोड़ा जाएगा। ऐसे में फाइनल कीमत 66,700 रुपये से ज्यादा ही बनेगी, समझिए हिसाब-

सोने की कीमत= 60,030 रुपये (6670 रुपये प्रति ग्राम X 9 ग्राम)

मेकिंग चार्ज= 6,603 रुपये (सोने की कुल कीमत पर 11 प्रतिशत)

जीएसटी= 1998.99 रुपये (60,030 रुपये+6,603 रुपये=66,6336 रुपये पर 3 प्रतिशत)

हॉलमार्किंग- 45 रुपये

फाइनल बिल= 68,676 रुपये

अब यही गोल्ड चेन बेचने जाएंगे तो मेकिंग चार्ज की वजह से सारा हिसाब अलग हो जाएगा।

PPF में निवेश करके आप भी बन सकते हैं करोड़पति, समझें पूरा कैलकुलेशन

इनकम सोर्स कभी बंद न हो यह हर व्यक्ति चाहता है। इसके लिए वह जब जॉब या बिजनेस करता है तो अपने रिटायरमेंट को सिक्योर करने के लिए कई जगह पर निवेश करता है। रिटायरमेंट स्कीम के लिए वैसे को कई स्कीम्स मौजूद है पर लोगों के बीच में पीपीएफ स्कीम काफी पॉपुलर है। इस आर्टिकल जानते हैं कि पीपीएफ कैसे करोड़पति स्कीम है।

नई दिल्ली। रिटायरमेंट के बाद भी इनकम सोर्स जारी रहे इसके लिए वैसे तोसरकार द्वारा संचालित पीपीएफ स्कीम नौकरीपेशा लोगों के बीच खासी लोकप्रिय है और इसमें निवेश पर जोरदार ब्याज के साथ ही कई तरह के एक्स्ट्रा बेनेफिट्स भी मिलते हैं. कई सेविंग स्कीम्स मौजूद हैं। लेकिन, इनमें से पब्लिक प्रोवीडेंट फंड (PPF) काफी पॉपुलर स्कीम है। इस स्कीम के जरिये आपक एक समय के बाद एकमुश्त राशि का लाभ मिलता है। ऐसे में सवाल है कि क्या इस स्कीम के जरिये भी करोड़पति बन सकते हैं। इसका जवाब हां है।

हर महीने बेसिक निवेश के जरिये आप भी पीपीएफ के माध्यम से करोड़पति बन सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि इसके लिए हर महीने कितने रुपये बचाने होंगे।

पीपीएफ में मिलता है जोरदार ब्याज

पीपीएफ स्कीम (PPF Scheme) के बेनिफिट की वजह से ही यह निवेशकों की पसंद है। अगर बाकी स्कीम्स यानी बैंक और पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की बात करें तो पीपीएफ में इन स्कीम्स की तुलना में ज्यादा ब्याज मिलता है। वर्तमान में सरकार इस स्कीम में 7.1 फीसदी का ब्याज दे रही है। यह ब्याद चक्रवृद्धि ब्याज होता है यानी ब्याज में भी ब्याज लगता है। ब्याज का कैलकुलेशन एनुअल होता है यानी पीपीएफ निवेशकों के अकाउंट में हर साल मार्च में पीपीएफ का ब्याज आता है।

पीपीएफ से कैसे बने करोड़पति

मूल से प्यारा ब्याज होता है। यह बात इस स्कीम में सच है। जी हां, हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे पीपीएफ के जरिये करोड़पति बन सकते हैं। यानी पीपीएफ एक तरह से करोड़पति स्कीम (Crorepati Scheme) है।

अगर आप पीपीएफ में हर महीने 405 रुपये का निवेश करते हैं तो इस हिसाब से आप साल में 1,47,850 रुपये का इन्वेस्ट करेंगे। अब इतनी ही राशि आप लगातार25 साल तक पीपीएफ अकाउंट में जमा करते हैं तो वर्तमान के ब्याज यानी 7.1 फीसदी ब्याज के हिसाब से भी आपके पीपीएफ फंड में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जमा होगी।

अपडेट हुए पेट्रोल-डीजल प्राइस, चेक करें कहां कितना सस्ता मिलेगा फ्यूल

रोजाना की तरह नए दिन की शुरुआत के साथ फ्यूल प्राइस भी अपडेट हो गए हैं। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक रविवार 8 सितंबर को भी राष्ट्रीय स्तर पर फ्यूल की कीमतों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। आप आज भी अपने शहर में पेट्रोल-डीजल पुरानी कीमत पर ही ले सकेंगे। मालूम हो कि सरकारी तेल कंपनियां रोजाना सुबह 6 बजे फ्यूल प्राइस रिवाइज करती हैं।

नई दिल्ली। भारत की तीनों ही सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने पेट्रोल और डीजल के रेट्स रिवाइज कर दिए हैं। इन कंपनियों ने घरेलू बाजारों के लिए फ्यूल की ताजा कीमतें, रविवार, 8 सितंबर के लिए अपडेट की हैं। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक आज भी फ्यूल की कीमतों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। आज भी पेट्रोल और डीजल पुरानी कीमतों पर ही खरीदा जा सकेगा।

पेट्रोल-डीजल पर नहीं लगता जीएसटी

मालूम हो कि पेट्रोल- डीजल पर जीएसटी नहीं लगता है लेकिन, पेट्रोल-डीजल का रिटेल सेलिंग प्राइस एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमिशन, वैट जुड़ने के बाद फाइनल होता है। अगर आप भी घर से बाहर गाड़ी लेकर निकल रहे हैं तो टंकी फुल करवाने से पहले पेट्रोल-डीजल का प्राइस चेक कर लेने की सलाह दी जाती है। इस आर्टिकल में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, अलग-अलग महानगरों और शहरों में पेट्रोल-डीजल की ताजा कीमत की जानकारी दे रहे हैं-

इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, अलग-अलग शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol- Diesel Price 8 September 2024)

चार महानगरों में पेट्रोल-डीजल के दाम

दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये और डीजल की कीमत 87.62 रुपये प्रति लीटर है।

मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.44 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 89.97 रुपये प्रति लीटर है।

कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104.95 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.76 रुपये प्रति लीटर है।

चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 92.34 रुपये प्रति लीटर है।

ये भी पढ़ें: रोजगार के बढ़ेंगे अवसर, एसीसी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में 90 अरब डॉलर के निवेश की उम्मीद

देश के दूसरे शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम

नोएडाः पेट्रोल 94.83 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.96 रुपये प्रति लीटर

गुरुग्रामः पेट्रोल 95.19 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.05 रुपये प्रति लीटर

बेंगलुरुः पेट्रोल 102.86 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.94 रुपये प्रति लीटर

चंडीगढ़ः पेट्रोल 94.24 रुपये प्रति लीटर और डीजल 82.40 रुपये प्रति लीटर

हैदराबादः पेट्रोल 107.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.65 रुपये प्रति लीटर

जयपुरः पेट्रोल 104.88 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.36 रुपये प्रति लीटर

पटनाः पेट्रोल 105.18 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.04 रुपये प्रति लीटर

विघ्नहर्ता से सीखें निवेश और बचत के मंत्र, इन्वेस्टमेंट के लिए पॉपुलर है एसआईपी

7 सितंबर 2024 को देशभर में गणेश चतुर्थी का त्योहार धूम-धाम से मनाया गया है। लोगों ने प्रार्थना की है कि भगवान गणेश उनके सारे विघ्न को हर ले। ऐसे में अगर वित्तीय जोखिम की बात करें तो भगवान गणेश से निवेश के साथ सेविंग से जुड़ी कई बातें सीख सकते हैं। वैसे बता दें कि निवेश के लिए अभी एसआईपी काफी अच्छा ऑप्शन है।

नई दिल्ली। 7 सितंबर 2024 को बड़ी धूमधाम से गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है। लोगों को उम्मीद रहती है कि भगवान गणेश उनके सभी विघ्न को हर लेंगे। जिस प्रकार भगवान गणेश हर बाधाओं को दूर करते है। ठीक उसी प्रकार हम निवेश के जरिये भी अपने वित्तीय परेशानी को एकहद तक कम कर सकते हैं।

अगर बात निवेश की हो तो म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) का नाम आता है। एसआईपी आज इन्वेस्टमेंट का काफी पॉपुलर माध्यम है। एसआईपी में क्यों निवेश करना चाहिए? यह जान लेने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि निवेश आखिर जरूरी क्यों होता है।

क्यों जरूरी है निवेश

भगवान गणेश हिंदू परंपरा में एक विशेष स्थान रखते हैं। हमारे जीवन से सभी 'विघ्नों' या बाधाओं को दूर करने की उनकी क्षमता के लिए उनकी पूजा की जाती है। ऐसे में अगर आज की आम जिंदगी देखें तो हम पाएंगे कि कई बार कई बार पर्याप्त फाइनेंस न होने की वजह से भी लोगों के सामने 'विघ्न' या बाधाएं आ जाती है। ऐसे में हमें समझदारी से निवेश का विकल्प चुनकर इन वित्तीय बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है।

निवेश करने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि सिर्फ सेविंग ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी की गारंटी नहीं देता है। इसकी वजह है महंगाई, बढ़ती महंगाई हमारी सेविंग की वैल्यू को लगातार कम कर रहा है। अगर हम भविष्य के लिए बड़ा फंड जुटाना या कह सकते हैं कि दौलत बनाना चाहते और अपना भविष्य वित्तीय रूप से सुरक्षित करना चाहते हैं तो हमें अपनी सेविंग को सही तरीके से निवेश करने की आवश्यकता है।

एसआईपी क्यों है बेस्ट ऑप्शन

कई बार लोग कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लिए टिप्स पर निवेश या सट्टा आधारित ट्रेडिंग का तरीका अपनाते हैं। इन गलत तरीकों को अपनाने की जगह म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना समझदारी है।

दरअसल, एसआईपी में आप बाजार के उतार-चढ़ाव से बेफिक्र होकर आसानी से नियमित रूप से एक फिक्स्ड राशि का निवेश करने और समय के साथ अपनी दौलत में इजाफा कर सकते हैं। इससे वित्तीय स्थिरता और ग्रोथ का रास्ता खुलता है।

एसआईपी (सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) के माध्यम से निरंतरता और निवेश में अनुशासन को लागू किया जा सकता है। एसआईपी आपको हर महीने केवल 10,000 रुपये का निवेश करके 20 साल में 1 करोड़ रुपये जमा करने में मदद कर सकता है (यह मानते हुए कि एनुअलाइज्ड रिटर्न 13% है)। रिटर्न की समान दर हो तो मंथली 45000 रुपये एसआईपी से सिर्फ 10 साल में 1 करोड़ रुपये जुटा सकते हैं।

सुरेश सोनी, सीईओ, बड़ौदा बीएनपी पारिबा एएमसी

गणेश सिखाते है कई फाइनेंशियल मंत्र

भगवान गणेश के बड़े कान हमें सिखाते हैं कि दूसरों की सलाह अच्छे से सुनना चाहिए। फाइनेंस की दुनिया में, इसका अर्थ बेहतर वित्तीय सलाह पर ध्यान देना या किसी योग्य फाइनेंशियल प्लानर/सेबी में रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श करना हो सकता है। वहीं, गणेश जी का बड़ा सिर ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक है। निवेश के मामले में, इसका अर्थ है पिछली गलतियों से सीखने की समझदारी और एक समझदार निवेशक बनना।

आपके पास है या खुलवाने की सोच रहे हैं लॉकर तो पहले पढ़ें आरबीआई के नए अपडेट

परिवहन विशेष न्यूज

कई लोग अपने जरूरी सामान यानी ज्वेलरी डॉक्यूमेंट रखने के लिए बैंक लॉकर का इस्तेमाल करता है। बैंक लॉकर के नियम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किये जाते हैं आरबीआई ने हाल ही में बैंक लॉकर के नई गाइडलाइन्स जारी की है। अगर आपके पास भी बैंक लॉकर है या आप लेने की सोच रहे हैं तो आपको बैंक लॉकर न्यू गाइडलाइन्स के बारे में जान लें।

नई दिल्ली। अपने ज्वेलरी या फिर कोई जरूरी डॉक्यूमेंट को घर में रखने या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के पास सुरक्षित रखवाने में हमें अक्सर डर रहता है। हमें डर रहता है कि अगर यह खो गए, चोरी हो गए या फिर जल गए तो जीवन भर की जमा-पूंजी व्यर्थ चली जाएगी। ऐसे में इन सभी की सिक्योरिटी के लिए बैंक लॉकर (Bank Locker) काफी अच्छा ऑप्शन रहता है।

अगर आप बैंक लॉकर लेने की या फिर आपके पास है तो आपको आज हम भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के नए अपडेट के बारे में बताएंगे। इन नए अपडेट के बारे में बताने से पहले हम आपको बता दें कि आरबीआई द्वारा ही बैंक लॉकर के नियम (Bank Locker Rule) तय किये जाते हैं। आरबीआई ने हाल ही में बैंक लॉकर के नियमों में कुछ बदलाव करते हुए गाइडलाइन जारी की है।

क्या है नई गाइडलाइन्स

आरबीआई ने लॉकर के रिन्यू करने का प्रोसेस बताया है। नए गाइडलाइन्स के हिसाब से 31 दिसंबर 2023 तक रिवाइज्ड एग्रीमेंट पर साइन करके बैंक में डिपॉजिट करना होगा।

क्या आप ओपन कर सकते हैं बैंक लॉकर

कई लोगों का सवाल होता है कि बैंक लॉकर किन्हें मिलता है। आरबीआई ने बताया कि बैंक लॉकर केवल उन खाताधारक को मिलता है जिनका बैंक में सेविंग अकाउंट (Savin Account) या करंट अकाउंट (Current Account) हो। अगर कस्टमर बैंक लॉकर ओपन करवाना चाहता है तो उसके लिए केवल पैन कार्ड (PAN card) या आधार कार्ड (Aadhaar card) की जरूरत होती है। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ भी जमा करना होता है।

बैंक लॉकर नियमों से जुड़ी अन्य बातें

लॉकर लेने के लिए बैंक और ग्राहक के बीच एग्रीमेंट होता है। इन एग्रीमेंट में सिग्नेचर करने के बाद ही लॉकर अलॉट किया जाता है।

लॉकर का साइज क्या होगा? यह ग्राहक द्वारा तय किया जाता है। वैसे तो बैंक लॉकर सिंगल-टायर्ड या मल्टी-टायर्ड होते हैं।

जब लॉकर ओपन हो जाता है तो बैंक कस्टमर को स्पेसिफिक नंबर की चाबी देता है और अपने पास उसका मास्टर चाबी (Master key) रखता है।

लॉकर पर कितना रेंट लगेगा यह इस बात पर तय किया जाता है कि लॉकर का साइज क्या है बैंक किस लोकेशन है। हालांकि, लॉकर ओपन होने के साथ ही बैंक कस्टमर से सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लेता है। यह डिपॉजिट फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed deposit) या कैश अमाउंट पर जमा किया जा सकता है।

रोजगार के बढ़ेंगे अवसर, एसीसी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में 90 अरब डॉलर के निवेश की उम्मीद

नई दिल्ली। एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी और इससे संबंधित उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भारत अगले पांच वर्षों में 90 अरब डॉलर (करीब 7.5 लाख करोड़ रुपये) का निवेश आकर्षित कर सकता है। उद्योग से जुड़े एक डाटा में आइएएसए की मांग पर सरकार ने एसीसी मैन्युफैक्चरिंग संयंत्रों की स्थापना और शुरू कराने में मदद के लिए विदेशी विशेषज्ञों को छह माह का वीजा देने की मंजूरी दे दी है। इस वीजा पर विदेशी विशेषज्ञ कई बार यात्रा कर सकेंगे और इसकी अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी। इसके अतिरिक्त इससे एसीसी आयात में खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

यह बात कही गई है। इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस (आइईएसए) के अनुसार, एसीसी मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में इस दौरान 50 हजार प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित करने की संभावना है।

आइएएसए की मांग पर सरकार ने एसीसी मैन्युफैक्चरिंग संयंत्रों की स्थापना और शुरू कराने में मदद के लिए विदेशी विशेषज्ञों को छह माह का वीजा देने की मंजूरी दे दी है। इस वीजा पर विदेशी विशेषज्ञ कई बार यात्रा कर सकेंगे और इसकी अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी। आइईएसए के प्रेसिडेंट देबी प्रसाद दाश ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे भारत में अगले पांच वर्षों में 100 गीगावाट घंटा से ज्यादा क्षमता के एसीसी बैटरी और बैटरी उपकरण संयंत्र स्थापित करने के अवसर सृजित होंगे।

इसके अतिरिक्त इससे एसीसी आयात में खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की बचत होगी और चीन व अन्य देशों पर भारत की निर्भरता कम होगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बनने के लिए भारत को ईवी और इसके उपकरणों के लिए एक व्यापक व स्वदेशी वैल्यू चेन विकसित करनी चाहिए। अभी भारत में एसीसी बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग प्रारंभिक चरण में है।

ईवी मैन्युफैक्चरिंग की करीब 50 प्रतिशत लागत एसीसी बैटरी से जुड़ी होती है। भारी उद्योग मंत्रालय 50 गीगावाट घंटा के स्वदेशी एसीसी मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित करने के लिए 2022 में PLI योजना लाया था।

भुबानेश्वर मे मेट्रो ट्रेन केलिए फारेस्टपार्कों सहित एयरपोर्ट के आसपास मिट्टी का परीक्षण भी किया गया है

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर: सार्वजनिक सड़कों पर मेट्रो ट्रेन की अवधारणा पर चर्चा के लिए पिछले अप्रैल में एक सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। इसके बाद ठप पड़ी मेट्रो ट्रेन का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। इस रेलवे विचार को फारेस्टपार्क से गुजारने के लिए पार्क से लगभग 400 पेड़ काटे जाएंगे। आज जब पार्क में पेड़ों को चिन्हित किया गया और मृदा परीक्षण किया गया तो इसका कड़ा विरोध हुआ।आज पार्कों सहित एयरपोर्ट के आसपास मिट्टी का परीक्षण भी किया गया है। जिस मार्ग में ओवरहेड कांसेप्ट बिखरा होगा उस मार्ग पर एक सौ से डेढ़ सौ मीटर के अंतराल पर ड्रिलिंग कर नमूने एकत्र किये जा रहे हैं। उसे जांच के लिए भेजा जाएगा। बताया गया है कि कल सड़क की मिट्टी की जांच करायी जायेगी। पिछले अप्रैल में रेलवे के निर्माण के लिए एक सार्वजनिक सर्वेक्षण किया गया था। सड़क के मध्य में पानी के पाइप, टेलीफोन लाइन, गैस पाइप लाइन, बिजली के खंभे सहित सभी 'उपयोगिताओं' को हटाने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया था। मध भवन से वलाबिहार तक 5.5 किमी लंबी स्मार्ट रोड पर लगभग 220 बिजली के खंभे हैं। ये सब हटा दिया जाएगा। गौरतलब है कि 6,255 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली मेट्रो रेल परियोजना 2027 तक पूरी हो जाएगी। सारा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। पहले चरण में यह मेट्रो रेल भुवनेश्वर हवाईअड्डे से त्रिशुल्वे चाचा तक 26 किमी तक चलेगी। इसमें 20 स्टेशन होंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) सलाहकार के रूप में इस परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है।

तुझ संग है मेरी प्रीत?

क्या? हार और क्या जीत,
तुझ संग है मेरी प्रीत?
चाहे जमाना जुदा करना चाहे,
तू ही तो है मेरा मन मीत।
क्या? तुझको है एहसास?
प्रेम गीत गाएंगे हम साथ।
विरह की कभी बात ना होगी,
जब भी तू मेरे साथ में होगी।
इश्क मैंने ऐसे ही नहीं किया है,
नैनो का रस हरदम पिया है।
एक-एक पल खूब जिया है,
सनम मेरे सिर्फ प्यार ही किया है।
अब, क्या? हार और क्या जीत,
तुझ संग बस है मेरी प्रीत?

संजय एम .तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)
98260-25986

एक युवती ने भुवनेश्वर के ओवरब्रिज से छलांग लगा दी

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुवनेश्वर : राजधानी समेत पूरे राज्य में गणेश पूजा की धूम के बीच आज एक दुखद घटना घटी है। एक युवती ने भुवनेश्वर के ओवरब्रिज से छलांग लगा दी है। युवती को गंभीर हालत में कैपिटल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवती ने किस वजह से छलांग लगाई, इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस अब घटना की जांच कर रही है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवती सेल्फी लेते समय गिरी या उसने जानबूझकर छलांग लगाई। हालांकि, बताया जा रहा है कि जब युवती की गाड़ी ओवरब्रिज पर दुर्घटनाग्रस्त हुई तो वह गाड़ी छोड़कर कूद गई।

-: रिटायर्ड बेचारा क्या करे :-

1. रिटायर व्यक्ति अगर देर तक सोया रहे तो....

बीवी : अब उठ भी जाइये ! आपके जैसा भी कोई सोता है क्या ? रिटायर हो गये तो इसका मतलब यह नहीं कि दोपहर तक सोते ही रहियेगा.... !

2. रिटायर व्यक्ति अगर जल्दी उठ जाये तो....

बीवी: आपको तो बुढापे में नींद पड़ती नहीं, दूसरों को तो सोना है न। एक दिन भी किसी को चैन से सोने नही देते हो, 5:30 बजे उठ कर बड़ बड़ करने लगते हो। अब तो आफिस भी नहीं जाना होता, चुपचाप सो जाइये और सबको सोने दीजिए..... !

3. रिटायर व्यक्ति अगर घर पर ही रहे तो....

बीवी: सबेरा होते ही मोबाइल लेकर बैठ जाते हो और चाय पर चाय के लिए चिल्लाते रहते हो, कुछ काम अपने से भी कर लिया कीजिए ।कभी घर से थोड़ा बाहर भी निकला करो, हमें भी चैन की सांस लेने दो। सब लोगों को कुछ न कुछ काम रहता है, यह आदमी दिन भर घर पर निठल्ला बैठा रहता है । यह नहीं होता है कि जल्दी से उठकर नहा धोकर नाश्ता पानी कर लें, अब इनके लिए सब लोग बैठे रहें.... !

4. रिटायर व्यक्ति अगर घर से देर तक बाहर रहे तो....

बीवी : कहाँ थे आप इतनी देर से ? अब नौकरी भी नही है, फिर भी घर पर टिकना नहीं होता। कभी अपने परिवार में भी बैठा करो। कभी मुँह से भगवान का नाम भी ले लिया कीजिए... !

5. रिटायर व्यक्ति अगर पूजा करे तो...

बीवी : ये घन्टी बजाते रहने से कुछ नहीं होने वाला। अगर ऐसा होता तो इस दुनिया के रईसों में टाटा या बिल गेट्स का नाम नहीं होता, बल्कि किसी पुजारी का नाम होता... ! जब देखो कभी माला कभी घंटी, कभी राम राम।

6. अगर रिटायर व्यक्ति खाली समय में पैसा कमाने के लिए कुछ काम करे तो...

बीवी : हर वक़्त काम, काम ,काम। ये पैसे की मोह माया बुढ़ापे में भी तुम्हे टिकने नहीं देती। हम क्या यहाँ पर बंधुआ मजदूर हैं जो सारा दिन काम करें और शाम को आपका इंतज़ार किया करें..... ?

7. रिटायर व्यक्ति अगर पत्नी को घुमाने के लिए किसी धार्मिक तीर्थ पर ले जाए तो...

बीवी : देखिये, सक्सेना जी अपनी बीबी को हर महीने घुमाने ले जाते हैं और वो भी शिमला और दार्जिलिंग जैसी जगहों पर, आपकी तरह रहरिद्वारह नहाने नहीं जाते.... !

8. रिटायर व्यक्ति अगर अपनी जिंदगी भर की बचत से नैनीताल, मसूरी, गोवा, माउन्ट आबू, ऊटी जैसी जगहों पर घुमाने ले भी जाए तो....!

बीवी : अपना घर ही सबसे अच्छा, बेकार ही पैसे लुटाते फिरते है। लगता है फालतू पैसे आ गये हैं आपके पास जो ज्यादा ही उछल रहे हैं। अब टिक कर भी बैठना है कि इधर उधर बंजारों की तरह घूमते ही रहना है। क्या रखा है घूमने में ? इतने पैसे से अगर घर पर ही रहते तो पूरे 2 साल के लिए कपड़े खरीद सकते थे, या फिर पूरे घर में पेंट करवा लेते !

9.रिटायर व्यक्ति पुराने गानों का शौक़ीन हो तो... !

बीवी: बुढ़ापे में गाने भाते हैं, अब ज्यादा जवानी चढ़ने लगी है, कोई भजन या राम के नाम ही ले लिया करो..... !

10.रिटायर व्यक्ति अगर मन बहलाने के लिए फोन करे तो....!

बीवी : दिन भर फोन पर लगे रहते हो, किस किस को फोन करते हो ? हम तो नहीं करते किसी को.....फोन !

11.रिटायर व्यक्ति बनठन कर घर में रहे तो....!

बीवी : बुढ़ापे में क्या सिंगार करते हो, जाना है कहीं क्या ? घर में ही सज धज कर बैठे रहते हो, बहुएं क्या कहेंगी... !

वाह रे ! रिटायर आदमी

सभी रिटायर्ड बंधुओं को समर्पित

ग्रेनो गाँवों के साथ भेदभाव में नॉएडा से आगे 124 गाँवों के विकास का नहीं है वेबसाइट पर विवरण

नोवरा ने लगाए आरोप , जल्द करें अपडेट नहीं तो होगा आंदोलन

परिवहन विशेष न्यूज

ग्रेटर नॉएडा। विकास प्राधिकरण के सहारे गाँवों को छोड़ने के सरकारों के वादों के बाद जनता को इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ रहा है , नॉएडा के बाद अब ग्रेटर नॉएडा प्राधिकरण द्वारा भी गाँवों के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार की बात सामने आयी है। नॉएडा विलेज रेसिडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रंजन तोमर ने संवाददाताओं से कहा की प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाने से ग्रामीण इलाकों सम्बन्धी विकास कार्यों का ब्यौरा पिछले 2017 -18 से अपडेट ही नहीं किया गया है। उन्होंने जब वेबसाइट पर गाँवों में हुए विकास कार्यों , प्रत्येक गाँव में कौन कौन से कार्य हुए हैं और उनका बजट क्या है। लेकिन इस बाबत कोई जानकारी वेबसाइट पर नहीं दिखी।

स्टेटस ऑफ़ विलेज डेवलपमेंट और प्लान ऑफ़ विलेज डेवलपमेंट कई साल से नहीं हुए अपडेट

प्लाट की स्कीम हो या पैसे कमाने का एक भी मौका , सभी जगह आजतक ही जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध गई लेकिन जब बात गाँव के विकास की हो तो वह कई वर्षों से अपडेट तक नहीं किया गया , वेबसाइट पर 2017 -18 का विवरण उपलब्ध है , जिसके बाद किसी तरह की जानकारी खूब छानबीन करने पर भी उपलब्ध नहीं है , जो बेहद दुखद है , हालाँकि कुल बजट की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है ,लेकिन गाँवों के हिसाब विकास कार्यों से कोई जानकरी वेबसाइट पर उपलब्ध नज़र नहीं आती , ग्रेटर नॉएडा प्राधिकरण के सीईओ को इसपर संज्ञान लेना होगा और त्वरित रूप से यह जानकारी लगातार अपडेट करवानी होगी जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के प्रति भी प्राधिकरण की जवाबदेही सिनिस्चित करवाई जा सके।

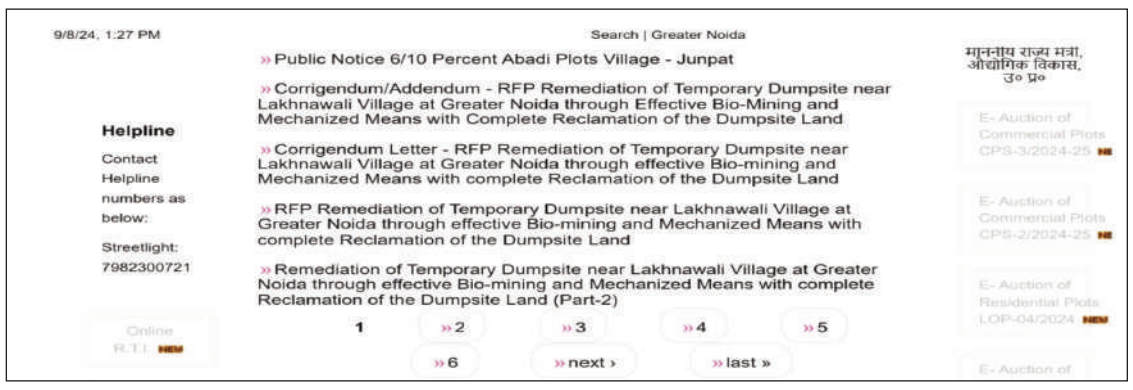

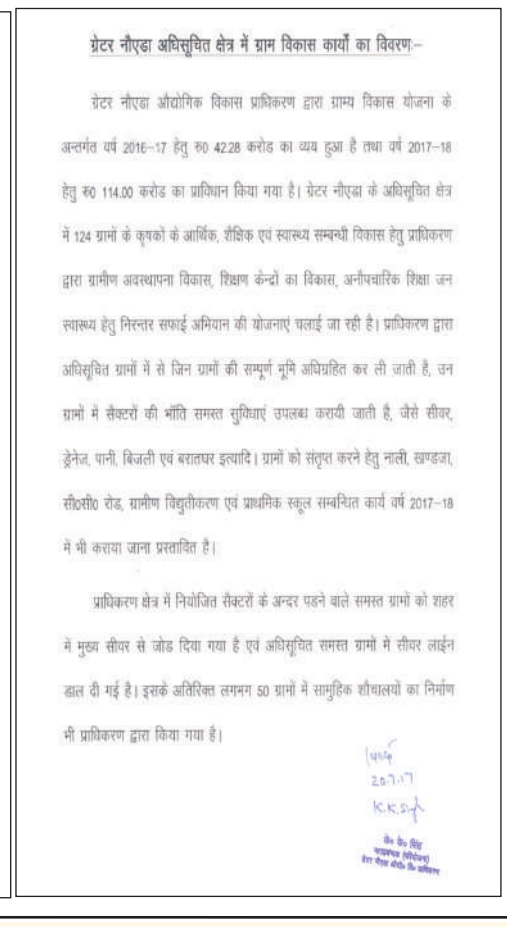

ग्रेटर नौएडा अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम विकास कार्यों का विवरण:-

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 हेतु रु0 42.28 करोड का व्यय हुआ है तथा वर्ष 2017-18 हेतु रु0 114.00 करोड का प्राविधान किया गया है। ग्रेटर नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र में 124 ग्रामों के कृषकों के आर्थिक, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी विकास हेतु प्राधिकरण द्वारा ग्रामीण अवस्थापना विकास, शिक्षण केन्द्रों का विकास, अनौपचारिक शिक्षा जन स्वास्थ्य हेतु निरन्तर सफाई अभियान की योजनाएं चलाई जा रही है। प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित ग्रामों में से जिन ग्रामों की सम्पूर्ण भूमि अधिग्रहित कर ली जाती है, उन ग्रामों में सैक्टरों की भाँति समस्त सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है, जैसे सीवर, ड्रेनेज, पानी, बिजली एवं बरातघर इत्यादि। ग्रामों को संतृप्त करने हेतु नाली, खण्डजा, सी0सी0 रोड, ग्रामीण विद्युतीकरण एवं प्राथमिक स्कूल सम्बन्धित कार्य वर्ष 2017-18 में भी कराया जाना प्रस्तावित है।

प्राधिकरण क्षेत्र में नियोजित सैक्टरों के अन्दर पड़ने वाले समस्त ग्रामों को शहर में मुख्य सीवर से जोड़ दिया गया है एवं अधिसूचित समस्त ग्रामों में सीवर लाईन डाल दी गई है। इसके अतिरिक्त लगभग 50 ग्रामों में सामुहिक शौचालयों का निर्माण भी प्राधिकरण द्वारा किया गया है।

सीरवी समाज शमसाबाद बडेर में श्री गणपती महाराज को विराजमान किया

परिवहन विशेष न्यूज

सीरवी समाज शमसाबाद बडेर प्रांगण में आज श्री गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर भगवान गणपति महाराज की विधि -विधान पूर्वक पूजा अर्चना करके विराजमान किया गया है। श्री गणेश जी महाराज से प्रार्थना की है अपनी कृपा दृष्टि हम सभी भक्तों पर बनाए रखें और हम सबके जीवन में रिद्धि-सिद्धि का संचार कर उन्नति को मार्ग पर चलने की नई ऊर्जा प्रदान करे। आज इस अवसर पर बडेर के संरक्षक -हरजी राम कोग, अध्यक्ष - आसाराम गहलोत, सचिव -भोलाराम पंवार, सहसचिव-नरेश परिहार कोषाध्यक्ष-राजुराम परिहार, सलाहकार -भूराराम परिहार, हरिराम परिहारीया, शिक्षा समिति के अध्यक्ष -केसाराम कोग, उपाध्यक्ष१ -भेराराम परिहारिया, सचिव - भीकाराम कोग, कोषाध्यक्ष -रमेश पंवार, कार्यकारिणी के सदस्य - तेजाराम चोयल, महिला मंडल के अध्यक्षा -पारी देवी कोग, उपाध्यक्ष १-सन्तोष देवी परिहार, उपाध्यक्ष २-गंगा देवी कोग, सभी भक्त गणों और बच्चों की महेती उपस्थिति में श्री गणपती महाराज को विराजमान किया गया है। अंत में भाव प्रसाद ग्रहण करके प्रस्थान किया।

शराब ने एक और जान ले ली

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा, भुवनेश्वर : शराब ने एक और जान ले ली। पुलिस ने मशानी से शव को जब्त कर लिया है और जांच कर रही है। दिगपहंडी ब्लॉक के विषमगिरी गांव gv में शराब के कारण एक और युवक की मौत होने की शिकायत परिवार और ग्रामीणों ने की है। खबर सुनने के बाद, स्थानीय पुलिस ने भीष्मगिरी कब्रिस्तान से शव को जब्त कर लिया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए बरहामपुर मेडिकल सेंटर भेज दिया है। मृतक भीष्मगिरी गांव के प्रेम नगर साहिर का 40 वर्षीय लड़का है। जानकारी के अनुसार, कृष्णा शुक्रवार को एक बकरी चोरी करने के लिए गंजाम गजपति सीमा क्षेत्र के बिचपट गांव गया था। ऐसा कहा जाता है कि वहां पकी हुई शराब पीने के बाद वह गंभीर रूप से बीमार हो गया। वह बिचपट गांव के एस. टिकरपाड़ा है। टिकरपाड़ा गांव जाने वाली नहर सड़क ब्रुंडावन नगर गांव के पास सड़क के किनारे पड़ी थी। वह उस रात घर नहीं लौटा। उसके बाद, परिवार के सदस्यों ने काफी देर तक उसकी तलाश की और सड़क के किनारे से उसका शव घर ले आए। इसके बाद सुबह कृष्ण के शव को अंतिम संस्कार के लिए पास के श्मशान घाट ले जाया गया। विशेष सूत्र से सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और शव को कब्जे में लिया। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस से शिकायत की कि उसकी मौत पकी हुई शराब पीने से हुई है। हालांकि, विशमगिरी, जुआनपल्ली, शमसुंदरपुर, मदल साही, बस्ता साही, उप साही, बादपुर, पलाझार, गोठकेली आदि गांवों में पकी हुई मां की बिक्री बड़े पैमाने पर होती है। लेकिन आबकारी और पुलिस शराब माफिया को पकड़ने में विफल रही है।

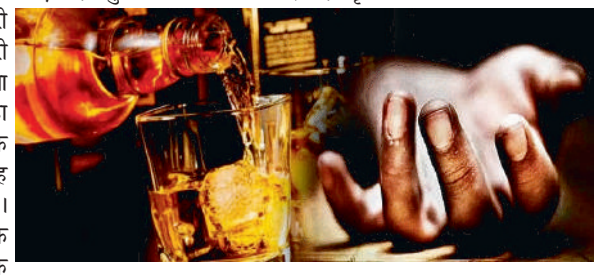

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी .आर .बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। **RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023**